मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

सांध्य दैनिक

रांची, मंगलवार, 4 अगस्त 2026

संवत 2083, श्रावण कृष्ण 6 मूल्य-3 रुपये

वर्ष-9, अंक 321, पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

4 ▶▶ विकसित भारत का रास्ता सुव्यवस्थित शहरों से संभव?

अपनी ही मौत से 24 घंटे पहले दिव्या भारती ने बोला था- मुझे बचाओ... सालों बाद सामने आया दिल दहला देने वाला सच! ◀ 6

अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या, सनसनी

चट्टान पर मिला शव,पहचान में जुटी पुलिस

मेट्रो रेज संवाददाता

बुंडू (राहे): राहे थाना क्षेत्र के ग्राम पारमडीह टुंगरीटोला गांव के समीप जारागोड़ा स्थित एक चट्टान पर मंगलवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक के गले पर धारदार हथियार से वार कर गला काटे जाने के स्पष्ट निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि मृतक के दाहिने हाथ पर केएम लिखा हुआ है, जिसे पहचान का महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने के साथ-साथ हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और विभिन्न थानों में गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान कराया जा रहा है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को मृतक की पहचान के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल राहे थाना या निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज,मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि गुरुजी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण

पैतृक गांव नेमरा में श्रद्धांजलि सभा, जेएमएम ने गुरू जी को किया याद

संवाददाता

रांची : झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव नेमरा-लुकैयाटांड़ (रामगढ़) में आयोजित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में समर्थक, जनप्रतिनिधि और आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अवसर पर लुकैयाटांड़ स्थित स्कूल परिसर में गुरुजी की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राज्य सरकार की ओर से झारखंड के सभी 24 जिलों में भी श्रद्धांजलि सभाएं और स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में गुरुजी के राजनीतिक जीवन, झारखंड आंदोलन में उनके योगदान और राज्य निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया जाएगा।

पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर शिबू सोरेन की तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें लिखा है कि स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी अमर रहें! जय झारखंड!। तस्वीर में उनके विचार भी साझा किए गए हैं, जिसमें शिबू सोरेन ने कहा था कि शिक्षा ही अपने अधिकारों की रक्षा करने और सामाज को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा हथियार है।

गौरतलब है कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे और उन्होंने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उनकी पहली पुण्यतिथि पर पूरा राज्य उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

न्यूज IN ब्रीफ

अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 3700 बोतल शराब बरामद

चतरा : चतरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 12 चक्का ट्रक से करीब 16 लाख रुपये मूल्य की 3700 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। शराब की यह खेप ट्रक में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही थी।

एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने सोमवार को सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसपी अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक से तस्करी के उद्देश्य से भारी मात्रा से शराब बिहार की ओर ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर उनके नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम में सदर थाना प्रभारी अनिल उरांव, पुअनि राहुल सिंह, सअनि रवि रंजन कुमार व प्रवीण कुमार शामिल थे। टीम ने शेरेगड़ा के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रक चालक ने पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस की वाहन जांच से बचने के प्रयास में ट्रक चालक तेज रफ्तार से भाग निकला, लेकिन कुछ ही दूरी पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में छिपाकर रखी गई शराब सड़क पर बिखर गई। एसडीपीओ ने बताया कि ट्रक के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध शराब चतरा होते हुए बिहार भेजी जा रही है।

वाहन जांच के दौरान संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा। पुलिस ने जब उसे रोकने का संकेत दिया तो चालक वाहन की रफ्तार बढ़ाकर भाग निकला। इसके बाद पुलिस टीम ने ट्रक का पीछा शुरू कर दिया। भागने के क्रम में संघरी घाटी मोड़ के पास चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया।

धान के भूसे में छिपाकर की जा रही थी शराब की तस्करीः पुलिस जब दुर्घटनास्थल पर पहुंची तो ट्रक का डाला धान के भूसे से भरा हुआ मिला। जांच के दौरान पता चला कि भूसे के नीचे बड़ी संख्या में शराब की पेटियां छिपाई गई थीं। ट्रक पलटने के कारण भूसा हट गया और शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। तस्करों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए बेहद शातिर तरीके से शराब को भूसे के अंदर छिपाया था।

ट्रक नंबर के आधार पर तस्करों की तलाशः एसडीपीओ ने बताया कि जांच के दौरान 3700 बोतल शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपये आंकी जा रही है। ट्रक चालक घटना के बाद फरार हो गया है। ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तस्करों की पहचान की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप किस राज्य से लाई गई थी और बिहार में किस गिरोह तक पहुंचाई जानी थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है। फरार चालक और शराब तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है।

मृत शिक्षक के नाम पर 14.65 लाख की फर्जी निकासी, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

बोकारो : जिले के शिक्षा विभाग में करोड़ों के सरकारी फंड के दुरुपयोग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है । पेटरवार प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सदमाकला के दिवंगत शिक्षक के नाम पर 14.65 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि की कथित रूप से फर्जी निकासी किए जाने का खुलासा हुआ है । शिक्षक की मौत के करीब तीन साल बाद उनके एरियर (अंतर वेतन वृद्धि) के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर राशि का भुगतान कर दिया गया. मामले के सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है ।

2021 में हुई थी शिक्षक की मौत, 2024 से 2026 के बीच निकाली गई राशिः जानकारी के अनुसार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सदमाकला में पदस्थापित शिक्षक संतोष कुमार शर्मा का निधन 14 अगस्त 2021 को हो गया था । इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान उनके नाम पर एरियर भुगतान दशार्ते हुए तीन अलग-अलग बिल तैयार किए गए और कुल 14.65 लाख रुपये से अधिक की राशि की निकासी कर ली गई ।

तीन बिलों के जरिए हुई निकासी

दस्तावेजों के अनुसार राशि तीन किश्तों में निकाली गई–

बिल संख्या 63/2024-25 : 5.16 लाख रुपये

बिल संख्या 77/2024-25 : 4.31 लाख रुपये

बिल संख्या 22/2025-26 : 5.17 लाख रुपये

बिलिंग असिस्टेंट पर निजी खाते में राशि ट्रांसफर कराने का आरोप

मामले में विभाग के बिलिंग असिस्टेंट मुकेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं । आरोप है कि उन्होंने दिवंगत शिक्षक के एरियर के नाम पर फर्जी बिल तैयार कराए और स्वीकृत कराकर तीनों किश्तों की राशि शिक्षक के परिजनों या अधिकृत खाते में भेजने के बजाय अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करा ली ।

प्रशासनिक प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग और कोषागार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं । एक ही दावे के आधार पर अलग-अलग समय पर तीन बिल कैसे तैयार हुए, उन्हें कोषागार से स्वीकृति कैसे मिली और भुगतान से पहले दस्तावेजों का सत्यापन क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं । जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इन भुगतानों को नियमसंगत बताने के लिए एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था । इससे आशंका जताई जा रही है कि मामले में विभाग के अन्य अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है । फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

बिजली संकट पर भड़के सांसद कालीचरण सिंह,अधिकारियों को दी आंदोलन की चेतावनी

चतरा : जिले में गहराते बिजली संकट और लचर आपूर्ति व्यवस्था पर चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विद्युत नियामक बोर्ड के चेयरमैन सह अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर बदहाल स्थिति से अवगत कराया। सांसद ने कहा कि चतरा को जरूरत की तुलना में महज आधी बिजली मिल रही है। क्षेत्र में 4 से 5 घंटे ही बिजली रहने से छात्रों की पढ़ाई और किसानों की सिंचाई ठप पड़ गई है। टंडवा में बिजली उत्पादन के बावजूद स्थानीय कटौती जारी है, जबकि लावालौंग में सेंचुरी एनओसी के नाम पर काम रोका गया है। उन्होंने डाढ़ा सब-स्टेशन को पावर ग्रिड से जोड़कर रोजाना 20 से 22 घंटे बिजली देने की मांग की। सांसद ने चेतावनी दी कि नियमित बिल चुकाने वाली जनता को पूरी बिजली न मिलना अन्याय है और सुधार न होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे।

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का आज पैतृक गांव नावाडीह में होगा अंतिम संस्कार, भारी पुलिस बल तैनात

मेट्रो रेज

पलामू/जामताड़ा : चर्चित गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार आज मंगलवार को उसके पैतृक गांव नावाडीह, हुसैनाबाद प्रखंड, पलामू में किया जाएगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका शव आज दोपहर करीब 12 बजे तक गांव पहुंचने की संभावना है।

परिवार के अनुसार गांव के बाहर कररबार नदी के तट पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में सुजीत सिन्हा की मां, भाई-बहन और पुलिस हिरासत में बंद उसकी पत्नी रिया सिन्हा के भी शामिल होने की उम्मीद है। रिया सिन्हा फिलहाल चाईबासा जेल में बंद है। उसे विशेष अनुमति मिलने पर ही अंतिम संस्कार में लाया जाएगा।

शांति व्यवस्था के लिए कड़ी सुरक्षा : सुजीत सिन्हा के आपराधिक इतिहास और कुख्यात छवि को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों की निगरानी में अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी।

साहिबगंज से धनबाद शिफ्टिंग के दौरान हुआ था एनकाउंटर : यह घटना रविवार रात जामताड़ा जिले में हुई थी। पुलिस के अनुसार सुजीत सिन्हा को कड़ी

सुरक्षा के बीच साहिबगंज जेल से धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। रास्ते में जामताड़ा के पास सुजीत ने भागने की नीयत से पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से सुजीत सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का लगाया आरोप : वहीं सुजीत सिन्हा के परिजनों ने पुलिस के दावे को खारिज किया है। सुजीत की सास उषा देवी ने इसे फर्जी मुठभेड करार देते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर वरीय अधिकारियों को भेजी गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जेपीएससी- जेएसएससी पर आंदोलन तेज

हजारों छात्रों ने फ्लैशलाइट जलाकर किया प्रदर्शन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का एलान

संवाददाता

रांची : राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में अभ्यर्थियों और छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को आंदोलन के दसवें दिन छात्रों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराते हुए शाम करीब सात बजे हजारों की संख्या में अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

सीबीआई जांच और एजेंसी पर कार्रवाई की मांगः आंदोलनकारी छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की सभी विवादित परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीडीपीएल का लाइसेंस रद्द कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित किए बिना युवाओं के साथ न्याय संभव नहीं है।

छात्र नेताओं ने रखी अपनी बातः फ्लैशलाइट प्रदर्शन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र नेता रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि छात्र पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी जांच के नाम पर कई निर्दोष शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच आवश्यक है।

10 अगस्त को विधानसभा घेराव का एलान3 छात्र नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की लड़ाई है। उन्होंने राज्य के सभी अभ्यर्थियों और युवाओं से 10 अगस्त को बड़ी संख्या में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचने की अपील की। इसके बाद विधानसभा घेराव कर अपनी एकजुटता और लोकतांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

हंटरगंज के ग्रामीणों की मानवीय पहल

लावारिस हालत में मिली मासूम बच्ची को सुरक्षित पहुंचाया थाना

बच्ची की पहचान के लिए पुलिस ने जनता से मांगा सहयोग

संवाददाता

चतरा : हंटरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को इंसानियत और सामाजिक संवेदनशीलता की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। क्षेत्र में लावारिस एवं असहाय अवस्था में भटक रही एक मासूम बच्ची को ग्रामीणों ने सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और बिना देर किए हंटरगंज थाना पहुंचाया। फिलहाल बच्ची पुलिस की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित है तथा उसकी देखभाल की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बच्ची क्षेत्र में अकेली और असहाय स्थिति में मिली थी। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित थाना

पहुंचाया। ग्रामीणों की इस संवेदनशील पहल की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं।हंटरगंज थाना पुलिस ने बच्ची के परिजनों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों से उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है। जब तक बच्ची अपने परिवार से नहीं मिल जाती, तब तक उसकी सुरक्षा, भोजन और अन्य आवश्यक देखभाल की पूरी व्यवस्था थाना परिसर में की गई है।

भद्रकाली मंदिर में सावन की पहली सोमवारी को शहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक को उमड़ी भीड़

चतरा : जिले के इटखोरी प्रखंड के भद्रकाली मंदिर परिसर में सावन के पहली सोमवारी पर जलाभिषेक को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। सोमवारी के मौके पर अहले शुबह से ही माता के मंदिर में पुजा अर्चना करने के पश्चात शहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने की भीड़ उमड़ने लगी । दो बजे रात से ही विभिन्न गांवों से भक्तों ने डीजे साउण्ड के साथ नाचते गाते माँ भद्रकाली के छठ घाट में डुबकी लगाकर कांवर में जल भर कर 1008 शहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। तत्पश्चात जल लेकर पुनः गांव के शिवाले में जलाभिषेक किया । सावन के पहली सोमवारी के मौके पर प्रखण्ड के अन्य शिवालयों में भी बाबा भोले का जलाभिषेक किया गया । मालुम हो की शहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में एक ही बार जलाभिषेक करने से 1008 शहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है जो विश्व में दुर्लभ है और विख्यात है । इसी कारण दूर दराज से श्रद्धालु अब कांवर लेकर शहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते है।

पानी से भरे गड्ढे में डूबने से महिला की दर्दनाक मौत

संवाददाता

चतरा : जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के तरवागाड़ा पंचायत अंतर्गत राहरबार नहर के समीप सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 52 वर्षीय विधवा महिला रामपतिया देवी की मौत हो गई। मृतका की पहचान राहरबार गांव निवासी स्वर्गीय विदेशी दास की पत्नी के रूप में हुई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से मुआवजे और कार्रवाई की मांग की।परिजनों के अनुसार रामपतिया देवी वर्षों से गांव में प्रसव कराने का कार्य करती थीं। सोमवार सुबह वह गांव के शंभू भुइयां के घर प्रसव कराने गई थीं। प्रसव कराने के बाद वह नहर किनारे स्थित पानी से भरे गहरे गड्ढे के पास कपड़े धोने पहुंचीं। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गईं। सामने से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें डूबते देखा और बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए।ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि गोलाई नहर से सुग्गी गांव तक चल रहे निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा मिट्टी निकालने के लिए कई गहरे गड्ढे खोदे गए थे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इन गड्ढों को नहीं भरा गया। बारिश का पानी भर जाने से ये गड्ढे अब जानलेवा बन चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन गड्ढों को भर दिया जाता, तो यह हादसा टाला जा सकता था।घटना की सूचना मिलने पर हंटरगंज पुलिस इंस्पेक्टर सह प्रभारी थाना प्रभारी विपिन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चतरा भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है।बताया जाता है कि रामपतिया देवी के पति का तीन वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। पति की मौत के बाद वह प्रसव कराने का कार्य कर अपने दो पुत्रों और एक पुत्री का पालन-पोषण कर रही थीं। उनकी असामयिक मौत से दो पुत्रों और एक पुत्री के सिर से मां का साया उठ गया, जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे और आर्थिक संकट में आ गया है।घटना की सूचना मिलने पर मुखिया प्रतिनिधि दिलीप दास भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने तथा नहर किनारे बने सभी जानलेवा गड्ढों को तत्काल भरवाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं।

जेके इंटरनेशनल स्कूल के पूर्व प्राचार्य ,अकादमिक डायरेक्टर व शिक्षाविद् अभिमन्यु मिश्रा बने ओटीए कामटी में एएनओ

संवाददाता

मुंगेर : तारापुर प्रखंड के शिशुआ गांव निवासी एवं शिक्षाविद अभिमन्यु मिश्रा ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), कामठी (नागपुर) से राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के द्वितीय अधिकारी (एएनओ) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर मुंगेर जिले का गौरव बढ़ाया है। वर्तमान में वह 4 बिहार बटालियन एनसीसी, भागलपुर से जुड़े हैं तथा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग, भागलपुर में कार्यरत हैं। इससे पूर्व वह जेके इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य एवं शैक्षणिक निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

प्रशिक्षण के दौरान अभिमन्यु मिश्रा को अर्जुन कंपनी में स्थान मिला। यहां कंपनी कमांडर निखिल पेंडारकर तथा मेजर आदित्य प्रताप सिंह (शौर्य चक्र, सेना पदक) के मार्गदर्शन में उन्हें सैन्य अनुशासन, राष्ट्रभक्ति तथा ₹नाम, नमक और निशान के महत्व का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों महेंद्र मीणा, सुरेश, राजीव, नागार्जुन, जीवन, मनीष, निलेश, बैद्यनाथ, गुरुंग और रॉबर्ट ने सभी प्रशिक्षुओं को कठिन प्रशिक्षण देकर उत्कृष्ट अधिकारी बनने के लिए तैयार किया।

परेड प्रशिक्षण में सिख रेजिमेंट के बलजिंदर सिंह ने सभी प्रशिक्षुओं को उच्च स्तर का अभ्यास कराया, जिसका प्रदर्शन समापन परेड के दौरान देखने को मिला। वहीं सिख रेजिमेंट के ही रमणदीप सिंह ने भी अभिमन्यु मिश्रा का हर स्तर पर मार्गदर्शन कर उनका

उत्साहवर्धन किया।

प्रशिक्षण के दौरान अभिमन्यु मिश्रा को उत्कृष्ट मंच संचालन के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के मेजर जनरल सर्वजीत सिंह बख्शी द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी कमांडर निखिल पेंडारकर एवं मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने भी उनकी प्रतिभा और अनुशासन की सराहना की।

स्वर्गीय सुनील कुमार मिश्र के पुत्र अभिमन्यु मिश्रा बचपन से ही सेना के माध्यम से देश सेवा का सपना देखते रहे हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने दिवंगत पिता, गुरुजनों और परिवार को देते हुए कहा कि उनका जीवन लक्ष्य देश सेवा करना तथा तिरंगे का सम्मान सदैव ऊंचा बनाए रखना है।

अभिमन्यु मिश्रा की इस उपलब्धि से शिशुआ गांव सहित पूरे तारापुर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। परिजनों और शुभचिंतकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जेके इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल एवं गौरवपूर्ण भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

हिंदपीढ़ी में असामाजिक तत्वों का उत्पात निजाम नगर में कई गाड़ियों में की तोड़फोड़

मेट्रो रेज

रांची: हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर में सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। सोमवार देर रात मोती मस्जिद रोड और मक्का मस्जिद रोड पर सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, गाड़ी के मालिकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बताया जाता है कि अज्ञात बदमाशों ने एक-एक कर कई वाहनों को निशाना बनाया। जिन वाहनों में तोड़फोड़ की गई उनमें हुंडई वरना, टाटा नेक्सॉन, स्कॉर्पियो, सूमो समेत अन्य गाड़ियां शामिल हैं। बदमाशों ने वाहनों के शीशे तोड़ने के बाद मौके से फरार हो गए।

मंगलवार सुबह जब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे तो उनके शीशे टूटे मिले। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया । लोगों ने तुरंत घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने कहा कि रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और क्षेत्र में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है उसमें एक कार पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है।

सूचना मिलने पर हिंदपीढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि तोड़फोड़ करने वाले आरोपितों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है।

अपर बाजार के दुकानदारों को हाईकोर्ट से राहत

निगम की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

संवाददाता

रांची: ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली अपर बाजार के दुकानदारों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने व्यवसायियों को राहत देते हुए रांची नगर निगम को अगले आदेश तक प्रार्थियों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अब मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पक्ष रखा।

यहां बता दें कि रांची नगर निगम ने अपर बाजार के करीब 6 व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस को रद्द कर दिया था और उन्हें व्यापार बंद करने और उनके दुकान को सील करने का नोटिस दिया था। जिसे दुकानदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से आज इस मामले को शीघ्र सुने जाने के आग्रह पर कोर्ट ने सुनवाई की।

रोजगार व अधिकारों की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी

गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं के नारों से गूंजी राजधानी रांची

मेट्रो रेज

रांची : झारखंड में रोजगार, शिक्षा और अपने अधिकारों की मांग को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-युवा, अभिभावक और सामाजिक संगठनों के लोग पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-मांदर और नागपुरी गीतों के साथ सड़कों पर उतरे। आंदोलन के दौरान गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं के नारे और गीत गूंजते रहे।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल नौकरियों का नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य की रक्षा का आंदोलन है। उन्होंने बिरसा मुंडा और सिद्धू-कान्हू के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह आज युवाओं को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा।

आंदोलन में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी ने लाखों युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा।

प्रिंस खान के दो कथित गुर्गों को हाईकोर्ट से जमानत रंगदारी और आर्म्स एक्ट मामले में मिली राहत

मेट्रो रेज

रांची: विदेश में रहकर कथित तौर पर गैंग संचालित करने वाले प्रिंस खान से जुड़े दो आरोपियों मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों आरोपियों को सदर थाना कांड संख्या 512/2025 से जुड़े मामले में राहत मिली है। इस मामले में दोनों पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए धमकी देने, आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है।

पुलिस के अनुसार, रांची पुलिस ने दोनों आरोपियों को 22 अक्टूबर 2025 को रिंग रोड इलाके से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से दोनों न्यायिक हिरासत में थे।

जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई सुनवाई: दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 20-20 हजार रुपये के दो-दो निजी मुचलकों पर जमानत देने का आदेश दिया।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि इसी मामले के एक अन्य आरोपी बबलू खान को भी झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जमानत प्रदान की थी।

हाईकोर्ट ने पीएलएफआई से जुड़े शुभम पोद्दार को दी जमानत

मेट्रो रेज

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पीएलएफआई से जुड़े शुभम पोद्दार को जमानत दे दी है। शुभम पोद्दार के खिलाफ खूंटी पुलिस ने 25 दिसंबर मार्च 2025 को खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र में क्रशर संचालक से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। शुभम पोद्दार पर आरोप है कि उसने पहले क्रशर संचालक से रंगदारी माँगी और फिर रंगदारी नहीं देने पर क्रशर में हवाई फायरिंग करवाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में शुभम को उसे 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर बेल दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुभम पोद्दार की बेल पर सुनवाई हुई। शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की। जिस मामले में शुभम को हाईकोर्ट से बेल मिली है वह खूंटी थाना से जुड़ा हुआ केस है जिसका कांड संख्या 235/2025 है।

खलारी से तीन मासूम रहस्मय ढंग से लापता, कई जिलों में तलाश जारी

अंतिम बार स्टेशन के पास देखने की सूचना

रांची: खलारी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित भुईयां टोली से तीन मासूम बच्चों के रहस्मय ढंग से लापता हो जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर टीएच कालोनी के समीप भुईयां टोली के दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे शिवा कुमार (10 वर्ष), मेघा कुमारी (6 वर्ष) और मंगल उरांव उर्फ टकला (9 वर्ष) रविवार शाम करीब पांच बजे सुभाष नगर स्थित शिव मंदिर परिसर में खेल रहे थे।

इसके बाद से तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। क्षेत्र के लोगों ने अपने स्तर पर बच्चों की खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच सूचना मिली कि तीनों बच्चों को खलारी रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के पास आखिरी बार खेलते हुए देखा गया था।इस सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला।घटना की सूचना खलारी थाना को दी गई है। पुलिस विभिन्न संभावित स्थानों पर बच्चों की तलाश कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। वहीं लापता हेल्प डेस्क की टीम भी खोजबीन में जुटी है।

जेपीएससी- जेएसएससी आंदोलन

प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत को तैयार सरकार, मंत्री सुदिव्य सोनू और गृह सचिव वंदना दादेल की देखरेख में बनेगी कमेटी

रांची: झारखंड सरकार जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात करने को तैयार है। इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य सोनू और गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल की देखरेख में हाई लेवल कमेटी बनेगी। इस कमेटी में कुछ मंत्री, नेता और आईएएस अधिकारी रहेंगे। यह कमेटी जल्दी ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी। इसके लिए गृह विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय मंगलवार को अधिसूचना जारी कर सकता है।

सोमवार की शाम बेंगलुरू से रांची लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। तय हुआ कि सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर छात्रों के साथ बातचीत करे, उनकी मांगों को समझे। इस कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह बातचीत कर आंदोलन को समाप्त कराने की कोशिश करे। गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी समेत कई अन्य परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। राज्यभर के छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे हैं। रविवार को उन्होंने मशाल जुलूस भी निकाला था। जुलूस के रूप में छात्र अल्बर्ट एक्का चैक पहुंचे, जहां जाम की स्थिति बन गई। इनका मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है।

झारखंड में इंटर पास स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार से मिलेगी छात्रवृत्ति

संवाददाता

रांची: केंद्र सरकार इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 2026 से 10,000 प्रतिवर्ष की स्कॉलरशिप देगी। यह योजना कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है, जिसमें झारखंड के 1878 विद्यार्थियों को कोटा मिलेगा।

केंद्र सरकार वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये देगी। इस स्कीम के तहत झारखंड के 1878 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित किया गया है। इस बाबत झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा ने केंद्रीय विवि, झारखंड (सीयूजे) सहित राज्य के सभी सरकारी विवि के कुलपति को पत्र भेजकर इस स्कीम के तहत अधिक से अधिक विद्यार्थियों से आवेदन कराने के लिए संबंधित कॉलेजों को दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया है।

इन विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति : अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण झारखंड का कोटा रिक्त रह गया। अध्यक्ष ने कहा है कि इस स्कीम के तहत वैसे विद्यार्थी, जो वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट कला, वाणिज्य व विज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों। साथ ही टॉप 20 परसेंटाइल के अंतर्गत आते हों। वैसे सभी मेधावी विद्यार्थियों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थी स्वयं लॉगिन कर अपना आइडी बना कर डाटा जमा कर सकते हैं।

छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी के माध्यम से : छात्रवृत्ति का भुगतान केंद्र द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे किया जायेगा। संबंधित विद्यार्थी को अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी, अंक पत्र, अपने बैंक का खाता विवरणी, आधार संख्या के साथ-साथ इंटरमीडिएट का रोल नंबर व रोल कोड (एक साथ 10 डिजिट में) लिखना है। डॉ हांसदा ने कहा है कि वर्ष 2024 के वैसे पूर्ववर्ती विद्यार्थी, जो पिछले वर्ष पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं, रिन्युएल के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान होने या नहीं होने पर किसी प्रकार का दावा जैक स्वीकार नहीं करेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग

अभिलेख हस्तगत 1941 नियम– 129
Eviction Suit No. 10/2023
मीना यादव
बनाम
रविन्द्र मुखर्जी वगैरह
–: नोटिस :–

प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष/विपक्षी– (1) रविन्द्र मुखर्जी, (2) माधुरी लता मुखर्जी,
पता– कैथोलिक आश्रम रोड, थाना– कोर्रा, जिला– हजारीबाग।

आवेदिका मीना यादव पे0 राम इकबाल राय, पता– कैन्टोमेंट, थाना– सदर, जिला– हजारीबाग के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से Jharkhand Building (Lease Rent and Eviction) Control Act. 2011 U/s- 19(1)(d) के तहत वकालतनामा के साथ आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन का अवलोकन किया गया। आवेदन के अनुसार मौजा– कैन्टोमेंट, थाना– सदर, जिला– हजारीबाग अन्तर्गत होल्डिंग नं0– 189/4, प्लॉट नं0– 654, रकवा– 08 डी0, भूमि में बना मकान में चार कमरा, एक बरामदा, एक किचन एवं एक बाथरूम को द्वितीय पक्ष के पिता के अच्छे व्यवहार होने के कारण बिना एग्रीमेंट के द्वितीय पक्ष के पिता को मासिक किराया 1,000/– (एक हजार) रूपये पर वर्ष 2015 में द्वितीय पक्ष के पिता को दिया गया था। दो वर्ष पहले द्वितीय पक्ष के पिता की मृत्यु के बाद विपक्षी के द्वारा किराया की राशि देना बन्द कर दिया गया है। बकाया किराया की माँग किए जाने पर टाल–मटोल किया जा रहा है तथा मकान खाली करने को कहा गया, तो विपक्षी के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। आवेदक द्वारा माह जनवरी 2020 से बकाया किराया की राशि एवं विपक्षी से घर खाली कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में आपको ज्ञापांक P/103, दिनांक 21/07/2022, ज्ञापांक P/279, दिनांक 03/07/2024, ज्ञापांक P/82, दिनांक 01/05/2024 एवं ज्ञापांक P/106, दिनांक 07/05/2026 को अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में कारण–पृच्छा दाखिल करने तथा उपस्थित होने का नोटिस निर्गत किया गया था। परन्तु आपके द्वारा आजतक न तो कारण–पृच्छा दाखिल किया गया और न हीं आप उपस्थित हो रहे हैं।

अतएव आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 27/08/2026 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कारण–पृच्छा दाखिल करें।

इसे सख्त ताकिद समझें।

यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 29/07/2026 को निर्गत किया गया।

भवन किराया नियंत्रक,
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर, हजारीबाग

PR 386509 District(26-27).D

सूक्ति

**सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर**

बच्चों की सेहत के पक्ष में अनुकरणीय पहल

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 1.08 लाख से अधिक स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का साहसिक और अनुकरणीय फैसला किया है। यह फैसला बच्चों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम कहा जाएगा। समोसा, वड़ा पाव, चिप्स, डीप-फ्राइड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट जैसे ज्यादा वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों को स्कूलों की सीमा से बाहर कर-के सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों का स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता में है। महाराष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कदम बढ़ाकर अन्य राज्यों के सामने भी नजीर पेश की है। बड़ा सवाल यह है कि देश के अन्य राज्य इस दिशा में कब तत्परता दिखाएंगे? क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी कर इस बारे में पहले ही चेतावनी दे दी है। दोनों संस्थानों के अध्ययन में पाया गया कि पिछले 14 साल में देश में जंक फूड की खपत 150 फीसदी बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह बच्चों में इसका बढ़ता आकर्षण है और उसके पीछे जंक फूड की सहज उपलब्धता और बच्चों को लुभाने वाले विज्ञापन हैं। बचपन की सबसे बड़ी पूंजी अच्छी सेहत होती है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली के कारण बच्चों की थाली से पारंपरिक और पौष्टिक भोजन गायब होता जा रहा है। इसका परिणाम कम उम्र में ही बच्चों में बढ़ते मोटापे, बाल-मधुमेह और जीवनशैली से जुड़ी अन्य गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। नीति आयोग और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने अनुमान जताया है कि यदि बच्चों के आहार पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक देश के 11 फीसदी बच्चे मोटापे और उससे होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। ऐसे में स्कूलों के भीतर और आसपास 'ईट राइट स्कूल' अभियान को सख्ती से लागू करने, खाने-पीने की चीजों के लिए एफएसएसएआइ लाइसेंस अनिवार्य करने और खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्ति के निर्देश अत्यंत व्यावहारिक हैं।

हालांकि, इस नीति की सफलता कागजी नियमों से ज्यादा धरातल पर इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। 50 मीटर के दायरे में रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानदारों पर लगातार निगरानी रखना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि केवल पाबंदी लगा देना ही काफी नहीं है। बच्चों को स्वस्थ विकल्पों की ओर आकर्षित करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक स्कूल कैंटीन में स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक बच्चों को जंक फूड से पूरी तरह दूर रख पाना कठिन होगा। देश को यदि अपनी युवा आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में जंक फूड के खिलाफ सख्त नीतियां बनानी होंगी। इसे एक जन-आंदोलन की तरह चलाया जाना चाहिए।

प्रकृति को जीवित विरासत मानने की जरूरत

राजस्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान केवल एक अभयारण्य नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के संतुलित सह-अस्तित्व की जीवंत मिसाल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह आर्द्रभूमि कभी हजारों प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गूंजती थी। साइबेरिया से लेकर मध्य एशिया तक के दुर्लभ पक्षी हर वर्ष यहां जीवन का उत्सव मनाने आते हैं, लेकिन आज वही घना अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिन जलाशयों में कभी पक्षियों का कलरव सुनाई देता था, वहां अब कीचड़, मृत मछलियां और कछुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य हमारी पर्यावरणीय सोच की विफलता का आईना है।

घाना की सबसे बड़ी जीवनरेखा पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से मिलने वाला पानी रहा है। पिछले कई वर्षों से कभी पानी देर से पहुंचा, कभी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा और इस वर्ष तो अब तक पानी पहुंचा ही नहीं। परिणामस्वरूप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट गहरा गया है। पक्षियों का आगमन प्रभावित हुआ है, जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है और जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। किसी विश्व धरोहर का इस स्थिति तक पहुंच जाना हमारी नीतिगत प्राथमिकताओं पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। विडंबना यह है कि देश के अनेक बांध, तालाब, झीलें और आर्द्रभूमियां भी इसी तरह दम तोड़ रही हैं। शहरों के विस्तार, अनियोजित विकास, अंधाधुंध खनन, अतिक्रमण और जल स्त्रोतों के अवैज्ञानिक दोहन ने प्राकृतिक जल चक्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। विकास परियोजनाएं बनाते समय पर्यावरण को अक्सर बाधा समझा गया, जबकि पर्यावरण ही सतत विकास की सबसे मजबूत नींव है। पर्यटन भी इस विरोधाभास का हिस्सा बन गया है। प्रकृति संरक्षण के नाम पर पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ तो दिखाई देती है, लेकिन उन पारिस्थितिकी तंत्रों को जीवित बनाए रखने की गंभीरता नहीं दिखती, जिनके कारण पर्यटन संभव हो पाता है। यदि जलाशय सूख जाएंगे, पक्षियों का आगमन बंद हो जाएगा और जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, तो विश्व धरोहर का दर्जा भी केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। प्रकृति की सुंदरता को जीवित विरासत मानने की जरूरत है।

केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का सूखना केवल भरतपुर की चिंता नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। विरासत केवल स्मारकों से नहीं बनती, बल्कि नदियों, जंगलों, तालाबों और उनमें बसने वाले जीव-जंतुओं से भी बनती है। यदि हमने आज भी विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश जारी रखा, तो आने वाली पीढ़ियों को किताबों में पक्षियों के नाम तो मिलेंगे, लेकिन उनके गीत सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी केवल इस विरासत का उपयोग करने की नहीं, बल्कि इसे और समृद्ध स्वरूप में अगली पीढि?ों को सौंपने की भी है।

विकसित भारत का रास्ता सुव्यवस्थित शहरों से संभव?

'यदि हमें भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है, तो दूरदर्शी नेतृत्व, वैज्ञानिक नियोजन, सक्षम संस्थाओं और अनुशासित क्रियान्वयन से गढ़ा जाए। मास्टर प्लान केवल भूमि उपयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि किसी शहर के भविष्य का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संविधान है। शहरों का भविष्य संयोग नहीं, सुनियोजित भौतिक नियोजन से बनता है। तीव्र शहरीकरण के दौर में दीर्घकालिक भौतिक विकास की अनिवार्यता है। जो शहर बिना योजना के बढ़ता है, वह अंततः जीवन, अवसर और गरिमा को बनाए रखने की अपनी क्षमता से आगे निकल जाता है।'

डॉ. रिपुन्जय सिंह

भारत के तीव्र शहरीकरण के दौर में दीर्घकालिक भौतिक नियोजन की अनिवार्यता है। किसी शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी दूरदृष्टि से होती है। जो शहर बिना योजना के बढ़ता है, वह अंततः जीवन, अवसर और गरिमा को बनाए रखने की अपनी क्षमता से आगे निकल जाता है। भारत आज विश्व के सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले देशों में है। हर वर्ष लाखों लोग बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन की आकांक्षा लेकर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। विकसित भारत का सपना भी मुख्यतः शहरों की उत्पादकता, नवाचार क्षमता और जीवन गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। हमने शहरों को बढ़ने दिया, लेकिन उन्हें विकसित नहीं किया। हमने निर्माण किया, परंतु नियोजन नहीं किया। हमने परियोजनाएं बनाईं, परन्तु शहर नहीं बना। परिणामस्वरूप आज अधिकांश शहर विकास और अव्यवस्था दोनों का समानांतर अनुभव कर रहे हैं।

हमारा शहरी विकास अभी भी प्रतिक्रियात्मक3 आज जब कहीं सडकें जाम हो जाती हैं, तब फ्लाईओवर बनते हैं। जलभराव होने पर नालों की सफाई होती है। भूजल समाप्त होने पर नए स्रोत खोजे जाते हैं। हरित क्षेत्र सिकुड़ने पर पौधरोपण अभियान चलाए जाते हैं। अनधिकृत बस्तियां विकसित होने के बाद नियमितीकरण की योजनाएं बनाई जाती हैं। अर्थात हमारा शहरी विकास अभी भी प्रतिक्रियात्मक है, जबकि आधुनिक शहरों का निर्माण पूर्वदर्शी और निवारक नियोजन पर आधारित होना चाहिए।

इसी सोच का परिणाम है कि अनेक शहरों में मास्टर प्लान होने के बावजूद विकास उसकी दिशा से भटक गया। योजनाएं कागजों पर रहीं और शहर बाजार, जनसंख्या और राजनीतिक निर्णयों के अनुसार फैलते चले गए। यह प्रवृत्ति न केवल शहरी अवसंरचना पर असहनीय दबाव डालती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, शहरी बाढ, जल संकट, वायु प्रदूषण और सामाजिक असमानताओं को भी गहरा करती है।

विकसित भारत 2047 का मार्ग केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि सुविचारित शहरी विकास से होकर गुजरता है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत परियोजना आधारित विकास से आगे बढकर योजना आधारित विकास को अपनाए। शहरों का निर्माण चुनावी कार्यकाल के पांच वर्षों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पांच पीढि?ों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

यही सोच है नियोजित विकास मॉडलों की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। इसी दृष्टि से 74वें संविधान संशोधन की भावना, नियोजन कानूनों के आधुनिकीकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान, जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन तथा नागरिक सहभागिता को भारत की शहरी विकास नीति का अभिन्न अंग बनाना होगा।

शहरों का भविष्य सुनियोजित भौतिक नियोजन से है बनताः यदि हमें भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है, तो दूरदर्शी नेतृत्व, वैज्ञानिक नियोजन, सक्षम संस्थाओं और अनुशासित क्रियान्वयन से गढ़ा जाए। मास्टर प्लान केवल भूमि उपयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि किसी शहर के भविष्य का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संविधान है। शहरों का भविष्य संयोग नहीं, सुनियोजित भौतिक नियोजन से बनता है। तीव्र शहरीकरण के दौर में दीर्घकालिक भौतिक विकास की अनिवार्यता है। जो शहर बिना योजना के बढ़ता है, वह अंततः जीवन, अवसर और गरिमा को बनाए रखने की अपनी क्षमता से आगे निकल जाता है।

आज हमारे अधिकांश शहर जाम, जल संकट, शहरी बाढ़, वायु प्रदूषण, अवैध कॉलोनियों, झुग्गी-बस्तियों, घटते हरित क्षेत्रों और कमजोर नागरिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। यह केवल बढ़ती जनसंख्या का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी दीर्घकालिक भौतिक योजना की कमजोरी और विकास की दूरदृष्टि के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

किसी भी शहर का भौतिक नियोजन केवल भवनों, सडकों और कॉलोनियों का नक्शा नहीं होता। यह उस शहर के अगले 20 से 30 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और आधारभूत विकास की व्यापक रूपरेखा होता है। भौतिक नियोजन यह निर्धारित करता है कि शहर किस दिशा में विकसित होगा, कहां आवासीय क्षेत्र होंगे, कहां उद्योग स्थापित होंगे, कहां विद्यालय, अस्पताल और पार्क बनेंगे, जल स्त्रोतों, पहाड़ियों, नदियों और हरित क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे होगी, परिवहन व्यवस्था किस प्रकार विकसित होगी, भविष्य की जनसंख्या के लिए भूमि और आधारभूत संरचना कहां सुरक्षित रखी जाएगी। यदि यह योजना पहले से न बनाई जाए तो विकास अव्यवस्थित हो जाता है और शहर अपनी वहन क्षमता से अधिक बोझ उठाने लगता है।

मास्टर प्लान भविष्य का रोडमैपः मास्टर प्लान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, भविष्य का रोडमैप है। जो शहर का भविष्य निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य केवल भूमि का उपयोग निर्धारित करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए रहने योग्य, सुरक्षित और समावेशी शहर तैयार करना है। दुर्भाग्य से भारत में अनेक मास्टर प्लान या तो वर्षों की देरी से तैयार होते हैं या उनके लागू होने तक वे पुराने पड़ जाते हैं। कई बार योजनाएं वास्तविक विकास की गति से पीछे रह जाती हैं और अनियोजित निर्माण उन्हें अप्रासंगिक बना देता है। किसी भी शहर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी भूमि का उपयोग कितना वैज्ञानिक है। यदि आवासीय क्षेत्र उद्योगों के निकट विकसित होंगे, यदि जलाशयों पर कॉलोनियां बसेंगी, यदि नालों और बाढ़ क्षेत्रों पर निर्माण होगा, यदि कृषि भूमि अनियंत्रित रूप से कंक्रीट में बदल जाएगी, तो शहर पर्यावरणीय संकट का शिकार होगा। आज अनेक शहरों में यही स्थिति दिखाई देती है।

जोनिंग नियमों की अनदेखी से किसी भी शहर में अनुशासित विकास की आधारशिला है। किंतु अनेक शहरों में भूमि उपयोग परिवर्तन, अवैध निर्माण,नियमों में बार-बार संशोधन तथा कमजोर प्रवर्तन ने इस व्यवस्था को कमजोर किया है। यदि नियमों का पालन समान रूप से न हो तो नियोजन केवल कागज तक सीमित रह जाता है। आधारभूत संरचना हमेशा विकास के पीछे है। अधिकांश शहरों में आधारभूत संरचना विकास के पीछे चलती है। यही कारण है कि नई बस्तियां वर्षों तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहती हैं।

जलवायु परिवर्तन ने शहरी नियोजन की परिभाषा बदल दीः विकसित देशों में पहले आधारभूत संरचना तैयार होती है, उसके बाद विकास की अनुमति दी जाती है। हमें भी यही मॉडल अपनाना होगा। परिवहन की सबसे बड़ी भूल है कि वाहनों के लिए शहर, लोगों के लिए नहीं हैं। हमारे अधिकांश शहर निजी वाहनों को ध्यान में रखकर विकसित हुए हैं। परिणाम सामने है जिनमें बढ़ता जाम, प्रदूषण, ईंधन की बबार्दी, समय की हानि, सडक दुर्घटनाएं आदि हैं। जबकि आधुनिक शहरी नियोजन का सिद्धांत स्पष्ट है। हम वाहनों को नही, लोगों को गतिशील बनाइए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट, पैदल मार्ग, साइकिल ट्रैक और सार्वजनिक परिवहन भविष्य के शहरों की पहचान हैं।

जलवायु परिवर्तन ने शहरी नियोजन की परिभाषा बदल दी है। अब शहर केवल आर्थिक केंद्र नहीं रहे। उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग भी बनना होगा। अत्यधिक वर्षा, शहरी बाढ़, सूखा, हीट वेव और भूजल संकट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं। भविष्य के शहरों में आधारभूत संरचना, वर्षा जल संचयन, शहरी वन, आर्द्रभूमियों का संरक्षण,पारगम्य सडकें, नवीकरणीय ऊजा, जल पुनर्चक्रण और हीट एक्शन प्लान को नियोजन का अनिवार्य भाग बनाना होगा।

भारत का भविष्य उसके शहरों मेंः हमारी शहरी विकास की सबसे बड़ी कमियां स्पष्ट हैं। जिनमे योजनाओं के बजाय परियोजनाओं पर अधिक ध्यान, दीर्घकालिक दृष्टि के स्थान पर अल्पकालिक राजनीतिक प्राथमिकताएं अनेक विभागों के बीच समन्वय का अभाव। पुराने आंकड़ों पर आधारित मास्टर प्लान, भूमि उपयोग नियमों का कमजोर पालन, नागरिकों की सीमित भागीदारी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रियल-टाइम डेटा का अपर्याप्त उपयोग, मास्टर प्लान का नियमित पुनरीक्षण न होना, जलवायु को नियोजन का अभिन्न हिस्सा न बनाना है। मास्टर प्लान स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवंत दस्तावेज बनने चाहिएए जिनकी प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा हो। शहरों की योजना केवल इंजीनियरों या योजनाकारों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिकों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों, उद्योग जगत और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से तैयार हो। भारत का भविष्य उसके शहरों में बसता है। यदि हमारे शहर सुव्यवस्थित होंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, निवेश बढ़ेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। लेकिन यदि शहर बिना दूरदृष्टि के बढ़ते रहे, तो वे स्वयं अपने विकास के सबसे बड़े अवरोध बन जाएंगे। आज आवश्यकता केवल नए मास्टर प्लान बनाने की नहीं है, बल्कि नियोजन की संस्कृति विकसित करने की है। हमें संकट आने के बाद समाधान खोजने की प्रवृत्ति से बाहर निकलकर भविष्य को पहले से समझने और उसी के अनुरूप शहरों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

महिला सुरक्षा कानून: कवच या हथियार?

'महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संभावित दुरुपयोग की प्रवृत्ति अब नए आयाम ग्रहण करती दिखाई दे रही है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की चिंता मुख्यत: वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में दहेज प्रताड़ना संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग पर केंद्रित रही है।'

डॉ. ऋतु सारस्वत

हाल ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने विक्रम कुमार झा उर्फ आर्यन आद्विक बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य मामले में एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न तथा अन्य धाराओं में दर्ज एफआइआर से संबंधित ट्रायल की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में उभर रही चिंताजनक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हाल के वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के निर्णय के बाद, जिसमें धारा 498 ए और 406 के मामलों में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया गया था, एक ऐसी प्रवृत्ति उभरती दिखाई दे रही है, जिसमें शिकायतकर्ता वैवाहिक विवादों में ससुराल पक्ष के लोगों पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा अन्य प्रकार के यौन दुराचार के गंभीर आरोप लगाने लगे हैं, जिससे उन्हें भारी धनराशि देकर समझौता करने के लिए विवश किया जा सके।' दिल्ली उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी स्पष्ट संकेत देती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संभावित दुरुपयोग की प्रवृत्ति अब नए आयाम ग्रहण करती दिखाई दे रही है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की चिंता मुख्यतः वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में दहेज प्रताड़ना संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग पर केंद्रित रही है। विशेष रूप से पति के परिवार के सदस्यों को, उनकी भूमिका से संबंधित विशिष्ट आरोपों के अभाव में भी, अभियुक्त बनाए जाने की प्रवृत्ति पर न्यायालय समय-समय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। बीते दिनों 'दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, 'भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का उद्देश्य पति अथवा उसके परिवार द्वारा महिला के साथ की जाने वाली क्रूरता से उसकी रक्षा करना और ऐसे मामलों में राज्य के त्वरित हस्तक्षेप को सुनिश्चित करना था। किंतु पिछले कुछ वर्षों में वैवाहिक विवादों में वृद्धि के साथ-साथ ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है, जिसमें पति एवं उसके परिजनों के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। सामान्य एवं अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पूरे परिवार को आपराधिक मुकदमे में घसीटना कानून की मंशा के अनुरूप नहीं है।' महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून, जैसे धारा 498ए, गंभीर सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लेकिन कई मामलों में इनके दुरुपयोग की घटनाओं ने न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ समाज और परिवारों पर भी व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाला है।

ऐसे मामलों में आरोपों का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और उसकी सामाजिक, मानसिक तथा भावनात्मक कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। गंभीर आरोपों की स्थिति में न्यायालय का मुकदमा तो बाद में चलता है, समाज का मुकदमा पहले शुरू हो जाता है। अनेक बार न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है, जबकि समाज अपनी धारणाओं के आधार पर। यहां एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उभरकर सामने आता है कि क्या न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है? क्या न्यायालय द्वारा निर्दोष सिद्ध किए जाने के बाद भी समाज द्वारा निर्मित धारणाएं सहजता से परिवर्तित हो जाती हैं?

विश्वास भय को खा जाता है

चिंतन-मनन

किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास उसकी सकारात्मक धारणाओं का कुल योग है। विश्वास एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो बार-बार के अनुभवों तथा प्रयत्नों से दृढ़ होता जाता है। विश्वास किसी साधारण धारणा से भिन्न है। विश्वास के आधार के बिना अनेक धारणाएं रखी जा सकती हैं, परंतु धारणाओं के आधार के बिना कभी विश्वास नहीं हो सकता। अतः विश्वास प्रायोगिक शोधों द्वारा विकसित तथा अनुभवों द्वारा सत्यापित एक रचनात्मक धारणा है। बार-बार विफल होने की वजह से उत्पन्न कष्ट, घृणा तथा भय की भावना, तथा यह भावना कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, ही युवकों को आलसी बनाती है। हमें प्रयास करना होगा कि बच्चे कुछ उपलब्धि कर सकें तथा विफलताओं से हतोत्साहित न हों, वे बारंबार प्रयास में प्रोत्साहित होकर अंततः सफलता प्राप्त करें। हमें इस बात का ध्या रखना होगा कि उनका आत्मविश्वास दिन-पर-दिन बढ़ता रहे। स्वामी विवेकानंद जी प्रायः कहते थे कि स्वयं पर विश्वास करो और सबल बनो। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, उसे नास्तिक कहा जा सकता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन आत्मबल की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। उनके अनुसार आत्मविश्वास केवल एक मानसिक गुण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का मूल आधार है। विवेकानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं में निहित असीम शक्ति को नहीं पहचानता, वह ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता को भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में उसी परमात्मा का अंश विद्यमान है। आत्म-अविश्वास वस्तुतः उस दिव्यता का निषेध है जो हमारे भीतर स्थित है। इसलिए सच्ची आध्यात्मिकता आत्मविश्वास से आरंभ होती है। जो व्यक्ति निडर होकर, दृढ़ता के साथ स्वयं पर भरोसा करता है, वही सच्चे अर्थों में सबल, आस्थावान और ईश्वर के निकट माना जा सकता है। स्वामी जगदात्मानंद कहते हैं कि जमीन पर रखे एक एक फुट चौड़े लकड़ी के पटरे पर एक बालक से चलने को कहो। वह निर्भय होकर उस पर चलता है। अब उसी पटरे को जमीन से बीस फीट ऊपर रखकर बालक से उस पर चलने को कहो। नीचे गिर जाने का भय उसके हृदय को जकड़ लेता है। कोई प्रोत्साहन-वाणी या पुरस्कार का प्रलोभन भी उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करता। पुरस्कार के आकर्षण के बावजूद भय उसकी इच्छाशक्ति पर हावी हो जाता है।

आपके पत्र

अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग न हो

लोकतंत्रीय व्यवस्था में संविधान के अनुसार हर नागरिक को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्ति/प्रदर्शन व अहिंसक/शांतिपूर्ण मार्च का अधिकार दिया गया है। किन्तु उसका बेजा उपयोग या दुरुपयोग कानूनी जुर्म होगा। अगर अभिव्यक्ति/प्रदर्शन अहिंसक और शांतिपूर्ण है तो सरकारी कानून-व्यवस्था का अनावश्यक उपयोग भी संविधान के अनुसार गैरकानूनी माना जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में पेपर लीक के मामले में सीजेपी द्वारा छात्रों को लेकर अहिंसक प्रदर्शन/आंदोलन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संज्ञान लेते हुए यही कहा है कि प्रदर्शनकारी हों या पुलिस, यदि किसी ने भी किसी पर अनावश्यक ज्यादती की है तो वे कानून के दायरे में आएंगे।

आरती वर्मा,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।
प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website : www.metrorays.in**
email : metrorays.ranchi@gmail.com

न्यूज IN ब्रीफ

जब्त शराब और गिरफ्तार युवक उत्पाद विभाग के हवाले

साहिबगंज : आरपीएफ ने मिजाचौकी रेलवे स्टेशन पर एक सन्दिग्ध युवक को ट्रेन पर चढ़ने के दौरान दबोच लिया जब जांच के क्रम में उसके पास से अवैध शराब बरामद हुआ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि आरपीएफ अक्षय कुमार ने एक संदिगध युवक को ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने के दौरान दबोच लिया। जांच के क्रम में उसके पास से देशी शराब बरामद हुई। पकड़ा गया युवक बिहार के भागलपुर जिला के सबौर थाना क्षेत्र का निवासी विक्की कुमार पाल 24 था। उसके पास से रॉयल झारखंड नामक देशी शराब की 25 बोतल बरामद हुई। शराब की कुल अनुमानित कीमत 1625 रुपये है। अग्रतर कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त शराब व गिरफ्तार युवक को उत्पाद विभाग के हवाले कर दिया गया।

जीजा ने साला समेत रिश्तेदारों पर मारपीट का लगाया आरोप, थाने में दिया आवेदन

साहिबगंज : नगर थाना क्षेत्र के एलसी रोड निवासी मोहम्मद कासिम अंसारी पिता- यासीन अंसारी ने अपने साला समेत अन्य रिश्तेदारों पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए नगर थाना में लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।आवेदन में कासिम अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके साला मोहम्मद आलमगीर उर्फ राजन, मो. आसीत, मो. जहागीर, मो. समीम, मो. जब्बार, मो. परवेज सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। उन्होंने मामले में सभी आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।वहीं मामले में दूसरे पक्ष की ओर से मोहम्मद आलमगीर उर्फ राजन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका जीजा मोहम्मद कासिम अंसारी रोज शराब के नशे में घर पहुंचकर हंगामा करता है और उनकी बहन के साथ मारपीट करता है। इसी कारण परिवार में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है।फिलहाल पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से जानकारी मिली है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

साहिबगंज उपायुक्त के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट संचालित किए जाने से सावधान रहें

साहिबगंज : जिला प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उपायुक्त, साहिबगंज श्री दीपक कुमार दुबे के नाम एवं फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आम नागरिकों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे फर्जी अकाउंट के माध्यम से भ्रामक संदेश झूठी सूचनाएँ अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन देकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा सकता है। जिला प्रशासन आमजनों से अपील करता है कि ऐसे किसी भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर विश्वास न करें, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक संबंधी विवरण अथवा धनराशि साझा न करें तथा किसी भी प्रलोभन में बिल्कुल न आएँ।उपायुक्त, साहिबगंज अथवा जिला प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ केवल अधिकृत एवं आधिकारिक माध्यमों से ही प्रसारित की जाती हैं। अतः किसी भी सूचना की सत्यता की पुष्टि केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही करें।यदि किसी नागरिक को उपायुक्त के नाम से संचालित कोई संदिग्ध अथवा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई देता है, तो उसकी जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएँ, ताकि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जिला परिषद ने मार्केट कॉम्पलेक्स आवंटन की प्रक्रिया की शुरू

हजारीबाग : जिला परिषद, हजारीबाग ने जिला परिषद पार्क के समीप स्थित नव निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स के खाली भवनों को किराये पर आवंटित करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले पात्र आवेदक को किया जाएगा। फर्म, संस्थान, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह तथा व्यक्तिगत आवेदक निर्धारित प्रारूप में मुहरबंद लिफाफे में 5 अगस्त 2026 को अपराह्न 2 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदनों की जांच एवं खुली बोली की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 को अपराह्न 3 बजे जिला परिषद की चयन समिति के समक्ष होगी। मार्केट कॉम्पलेक्स का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 26,772 वर्गफुट है, जिसमें भूतल एवं प्रथम तल शामिल हैं।

आवेदन पत्र, नियम-शर्तें तथा किराया, जमानत राशि व अन्य जानकारी जिला परिषद कार्यालय तथा हजारीबाग जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। जिला परिषद ने सभी पात्र इच्छुक आवेदकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

जिला परिषद ने मार्केट कॉम्पलेक्स आवंटन की प्रक्रिया की शुरू

हजारीबाग : जिला परिषद, हजारीबाग ने जिला परिषद पार्क के समीप स्थित नव निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स के खाली भवनों को किराये पर आवंटित करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले पात्र आवेदक को किया जाएगा। फर्म, संस्थान, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह तथा व्यक्तिगत आवेदक निर्धारित प्रारूप में मुहरबंद लिफाफे में 5 अगस्त 2026 को अपराह्न 2 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदनों की जांच एवं खुली बोली की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 को अपराह्न 3 बजे जिला परिषद की चयन समिति के समक्ष होगी। मार्केट कॉम्पलेक्स का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 26,772 वर्गफुट है, जिसमें भूतल एवं प्रथम तल शामिल हैं। आवेदन पत्र, नियम-शर्तें तथा किराया, जमानत राशि व अन्य जानकारी जिला परिषद कार्यालय तथा हजारीबाग जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। जिला परिषद ने सभी पात्र इच्छुक आवेदकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

सरकारी जमीन पर प्रशासन का चला बुलडोजर

हजारीबाग : सदर अंचल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए हुरहुरु क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में सोमवार को भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम हुरुहुरु पहुंची और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।

स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय उत्सव ही नहीं बल्कि समाज के उन व्यक्तियों के सम्मान का भी अवसर है : उपायुक्त

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को जिला प्रशासन करेगा सम्मानित

मुख्य समारोह स्थल पर अग्निशमन दल, मेडिकल टीम पेयजल सुरक्षा व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं रहेंगी उपलब्ध

संवाददाता

साहिबगंज : आगामी 80वाँ स्वतंत्रता दिवस-2026 के गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों एवं संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं समन्वित रूप से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।बैठक में बताया गया कि विगत वर्षों की परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी 15 अगस्त 2026 का मुख्य जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सिद्धो-कान्हो स्टेडियम, साहिबगंज में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण का समय भी निर्धारित किया जाएगा।उपायुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों, विभागों, सार्वजनिक संस्थानों व विद्यालयों के कार्यालय प्रधानों तथा प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय के अनुसार अपने-अपने कार्यालयों एवं विद्यालयों में मुख्य जिला स्तरीय समारोह से पूर्व ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पूर्णतः पालन किया जाए।इस दौरान माल्यार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि मुख्य समारोह स्थल स्थित सिद्धो-कान्हो की प्रतिमा पर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से माल्यार्पण करेंगे। वहीं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, शहीद भगत सिंह तथा भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर नगर परिषद, साहिबगंज के कार्यपालक पदाधिकारी माल्यार्पण करेंगे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर उप विकास आयुक्त तथा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुलिस उपाधीक्षक सदर द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रतिमाओं पर पर्याप्त संख्या में पुष्पमालाएं, साफ-सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की विधिवत व्यवस्था, मंच सज्जा, विशिष्ट अतिथियों एवं आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पेयजल, विद्युत व्यवस्था बैरिकेडिंग पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जबकि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाली परेड की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परेड का संपूर्ण संचालन एवं प्रबंधन पुलिस अधीक्षक, साहिबगंज के नेतृत्व में किया जाएगा। परेड में जिला सशस्त्र बल, जैप-9 के जवान, जैप-9 की महिला पुलिस बल, एनसीसी के महिला एवं पुरुष कैडेट्स तथा जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। जिसमें यह भी निर्णय लिया गया कि परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सभी प्रतिभागी दलों एवं एनसीसी कैडेट्स को सार्जेंट मेजर द्वारा परेड का अभ्यास कराया जाएगा, ताकि मुख्य समारोह के दौरान अनुशासन, समन्वय एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में देशभक्ति एवं जनभागीदारी का वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रातः 7:00 बजे से 8:00 बजे तक प्रभात फेरी आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को प्रभात फेरी के सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। परेड निरीक्षण हेतु वाहन की उपलब्धता, राष्ट्रीय गान के लिए गायन टोली की व्यवस्था, सलामी समारोह में भाग लेने वाले कैडेट्स के लिए परिवहन व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव एवं सम्मान का पर्व है। इसके आयोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्य समारोह स्थल पर अग्निशमन दल, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें ताकि समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2026 को संध्या 6:30 बजे टाउन हॉल, साहिबगंज में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में विद्यालयों एवं विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के कलाकार देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।उपायुक्त श्री दीपक कुमार दूबे ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय उत्सव ही नहीं, बल्कि समाज के उन व्यक्तियों के सम्मान का भी अवसर है जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, प्रशासनिक सहयोग तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस से पूर्व अपने-अपने कार्यालयों, परिसरों एवं भवनों की विशेष साफ-सफाई, रंग-रोगन, परिसर की स्वच्छता तथा सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय आकर्षक एवं व्यवस्थित दिखाई दें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया।बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता विजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, साहिबगंज अमर जॉन आईन्द, सिविल सर्जन रामदेव पासवान, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा : सतीश चंद्रा

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता व व्यवस्थाओं का लिया विस्तृत जायजा

संवाददाता

साहिबगंज : जिले में आमजन को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त, साहिबगंज श्री सतीश चंद्रा द्वारा आज सदर अस्पताल साहिबगंज का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं चिकित्सकीय सेवाओं स्वच्छता व्यवस्था दवा उपलब्धता और मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं का गहनता से अवलोकन किया।निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त ने आपातकालीन कक्ष चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी ओपीडी भवन पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, दवा वितरण केंद्र तथा अस्पताल परिसर की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से भी बातचीत कर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की उनकी समस्याओं व सुझावों को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, मरीजों को समय पर उपचार व आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अल्ट्रासाउंड एवं अन्य जांच सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित रखने मरीजों के साथ मानवीय व सम्मान जनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समयबद्ध, पारदर्शी एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी सेवा भावना के साथ कार्य करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।निरीक्षण उपरांत उप विकास आयुक्त ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. देवेश कुमार एवं सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अस्पताल की समस्त व्यवस्थाओं में सतत सुधार, नियमित अनुश्रवण तथा मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश दिए।

हर एक नागरिक नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा लेंगे : बिंदु

संवाददाता

साहिबगंज : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय साहिबगंज के जिरवाबाड़ी शाखा में 3 संस्था द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान का मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके इस अभियान को लांच किया गया।इस अभियान को 6 से 20 अगस्त तक शहर के सभी स्कूल,कॉलेज,जैप 9,मंडल कारा और भी कई स्थानों पर चलाया जाएगा ताकि हमारे बच्चे, युवा और हर एक नागरिक इस अभियान का हिस्सा बनकर नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा लेंगे।केंद्र संचालिका बी.के बिंदु दीदी ने कहा कि देश की युवा देश का भविष्य है खासकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। ब्रह्माकुमारी के द्वारा इस अभियान को 15 अगस्त 2020 से चलाया जा रहा है और अब तक कई लोगों ने इस अभियान के द्वारा नशा मुक्त जीवनशैली को अपनाने का संकल्प लिया और उसको साकार भी किया ।भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ ब्रह्माकुमारी संस्था ने 4 मार्च 2023 को एक विशेष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि इस अभियान के संदेश को जन-जन तक व्यापक रूप से फैलाया जा सके।केंद्र की उप-संचालिका बी. के नीतू ने सभी को राजयोग की शिक्षा प्रदान की और मेडिटेशन कराया।अंत मे अतिथियों के द्वारा प्रेरणादाई उद्बोधन दिया गया और नशा मुक्त रहने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई।मौके पर राजेश अग्रवाल,अजय यादव, डॉक्टर आर सी पंडित, राजेश यादव, राजेश सिंह, रतन सिन्हा,सुशीला देवी सहित कई लोग मौजूद थे।

साहिबगंज होकर चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन, यात्रा होगी आसान

साहिबगंज : रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने परीक्षा विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इनमें टाटानगरझरामपुर बाजार परीक्षा विशेष ट्रेन मालदा टाउन के रास्ते संचालित होगी, जो साहिबगंज रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। इससे साहिबगंज एवं आसपास के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी।रेलवे के अनुसार, यह विशेष ट्रेन पूर्व रेलवे क्षेत्र में डानकुनी, बर्द्धमान, बोलपुर शांतिनिकेतन, रामपुरहाट, पाकुड़, न्यू फरक्का और मालदा टाउन सहित निर्धारित स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान (स्लीपर) श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे, जिससे परीक्षार्थियों को सुविधाजनक यात्रा मिल सके।रेलवे ने बताया कि 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाली आरआरबी लेवल-1 सीबीटी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परिचालन और प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें अथवा अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। परीक्षा अवधि में रेलवे मुख्यालय और सभी मंडलीय मुख्यालयों में 247 संयुक्त कंट्रोल रूम संचालित किए जाएंगे। वहीं रेलवे सुरक्षा बल स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा केंद्रों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की निगरानी करेगा।इसके अलावा विद्युत तथा सिग्नल एवं दूरसंचार एस एंड टी विभाग के अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, सर्वर कक्ष और इंटरनेट व्यवस्था का पूर्व निरीक्षण करेंगे, ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए।रेलवे के इस निर्णय से साहिबगंज, पाकुड़ और आसपास के जिलों के हजारों आरआरबी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

फरार आरोपी के घर न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार चस्पा

साहिबगंज : जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा किया थाना क्षेत्र के चानन गांव निवासी विपिन साह, पिता महेंद्र साह, कांड संख्या 273/22 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है। सोमवार को न्यायालय से निर्गत इश्तेहार को आरोपी के घर पर विधिवत चस्पा किया गया और शीघ्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फरार आरोपी के घर इश्तेहार चस्पा किया गया है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बकाया मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं में आक्रोश

संवाददाता

साहिबगंज : झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार पहल करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा।इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शबाना आजमी ने की,जबकि बड़ी संख्या में सेविकाएं उपस्थित रहीं।ज्ञापन में सेविकाओं ने जनवरी 2026 से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान, जून 2026 से एरियर राशि का भुगतान, पोषाहार मद की बकाया राशि, अंडा मद की लंबित राशि और जून 2026 से पोषाहार चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई।सेविकाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। स्थिति

यह है कि कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं।उन्होंने कहा कि केंद्रों के संचालन को जारी रखने के लिए उन्हें स्थानीय दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करनी पड़ रही है।प्रदर्शन कर रही सेविकाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगी।उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु लंबित भुगतान तत्काल किया जाए,ताकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित न हों।ज्ञापन सौंपने के दौरान सेविकाओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में उनकी अहम भूमिका है,लेकिन लगातार उपेक्षा के कारण उनका मनोबल टूट रहा है। उन्होंने जल्द समाधान की उम्मीद जताई।इस अवसर पर सेविका रचना देवी,गीतू शर्मा,गीता देवी, सोनी खातून, शबनम आरा, नीलम ठाकुर, कश्मीरा आनंद सहित सैकड़ों सेविका उपस्थित हुई।

अपनी ही मौत से 24 घंटे पहले दिव्या भारती ने बोला था- मुझे बचाओ... सालों बाद सामने आया दिल दहला देने वाला सच!

बॉलीवुड की सबसे हसीन और दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की अचानक मौत आज भी उनके चाहने वालों के लिए एक अनसुलझी याद बनी हुई है। उनके निधन से जुड़े किस्सों और तथ्यों को जानने की उत्सुकता आज भी फैंस में बनी रहती है। बहुत कम लोग जानते हैं की जब उनका निधन हुआ, तब वह अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की शूटिंग कर रही थीं। उनके असामयिक निधन के बाद फिल्म की कहानी और शूटिंग का बड़ा हिस्सा दोबारा करना पड़ा। हाल ही में फिल्ममेकरअनीस बज्मी ने खुलासा किया कि वह दिव्या भारती के निधन से महज एक दिन पहले उनसे मिले थे। उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात से जुड़ी कुछ भावुक यादें साझा कीं, जिन्होंने एक बार फिर दिव्या भारती को लेकर पुरानी यादें ताजा कर दीं।

उनकी मौत के बाद 2 महीने तक किसी ने काम नहीं किया : हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान अनीस बज्मी ने बताया की वो समय हमारे लिए काफी दुखद था। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो ही चुकी थी और उन्होंने अपने किरदार को भी बहुत ही शानदार तरीके से निभाया था लेकिन इसके बाद क्लाइमैक्स की शूटिंग से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई सदमे में चला गया, किसी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। दिव्या की मौत के करीब 2 महीने तक किसी ने काम नहीं किया। उस फिल्म का 90 प्रतिशत हिस्सा शूट हो चुका था और पूरी टीम काफी परेशान थी कि आगे क्या किया जाए ? बहुत ज्यादा सोच-विचार करने के बाद उन्होंने फिल्म को दोबारा से शूट करने का फैसला किया।

एक नकाबपोश आदमी उन्हें घसीटकर ले जाता है: अनीस बज्मी ने बताया कि

आखिरकार मेकर्स ने फिल्म में दिव्या भर्ती की जगह श्रीदेवी को लेने का फैसला किया और प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू किया। मुताबिक, इस फैसले ने फिल्म को एक अलग पहचान दे दी। उन्होंने आगे कहा की दिव्या भारती के अचानक निधन की वजह से उनकी दो फिल्में लाडला और अंगरक्षक दोबारा शूट करनी पड़ी। अनीस ने याद करते हुए बताया कि अंगरक्षक की शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी और उस समय पूरी टीम चेन्नई में काम कर रही थी। दिव्या के निधन से ठीक एक दिन पहले उन्होंने उनके साथ एक सीन शूट किया था, दिव्या कैमरे से दूर जाती हैं और धीरे-धीरे फ्रेम से बाहर हो जाती हैं। उसी समय एक व्यक्ति आता है, जिसने अपना मुँह ढका हुआ है और वो उन्हें वहां से घसीटकर ले जाता है। इसके बाद दिव्या जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मुझे बचाओ... और अगले दिन उनका देहांत हो जाता है। इस खबर के बाद पूरी टीम सदमे में चली गई।

इसके बाद उन्होंने इस फिल्म के श्रीदेवी को रोल दिया। इसके बाद दोनों फिल्मों की शूटिंग की शुरूआत दोबारा से हुई।

'रामायण' से मिली फीस कैंसर पीड़ित बच्चों को दान करेंगे विवेक ओबेरॉय

विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर राम और साई पल्ल्वी सीता का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें की विवेक इस फिल्म में विद्युत्जि का किरदार निभाते हुए नजर आएँगे। इस फिल्म से ज्यादा विवेक अपने एक फैसले की वजह से लाइमलाइट में आ गए हैं। इस फिल्म से उन्हें जो भी पैसा मिलेगा वो फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए दान करेंगे।

कैंसर पीड़ित बच्चों को दान करेंगे सारी फीस : हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने नामित मल्होत्रा से कह दिया है कि वे रामायण फिल्म से मिली हुई फीस अपने पास नहीं रखेंगे। उनका मन है कि वो अपनी सारी फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए देंगे। इसी के साथ एक्टर ने कहा कि वह इस नेक पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके मुताबिक, 'रामायण' भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली फिल्म साबित हो सकती है, इसलिए वह इस सफर

में अपना योगदान देना चाहते हैं।

भारतीय सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट है 'रामायण' 3 इसी बीच विवेक ने रामायण फिल्म के प्रोड्यूसर ??और डायरेक्टर की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।

ओबेरॉय ने कहाः विवेक ओबेरॉय ने कहा कि नामित मल्होत्रा और नितेश तिवारी जिस स्तर पर काम कर हैं, वह भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनके अनुसार रामायण एक ऐसी फिल्म है जो भव्यता और तकनीक के मामले में हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देगी। उन्होंने बताया कि उस प्रोजेक्ट से एक ऐसी श्ऋकंपनी जुड़ी है, जिसे बहुत से ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। विवेक का मानना है की भारत की महान पौराणिक कहानी को वैश्विक स्तर पर पेश करने से बेहतर बात और क्या हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा की इस फिल्म में काम कर के उन्हें बहुत खुशी मिली है और पूरी टीम के साथ काम करना उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी रिवील किया कि फिल्म की कुछ दिनों की शूटिंग अभी बाकी है।

जारी हुआ 'मिजार्पुरः द मूवी' का गाना 'दो नंबरी' ढांडा न्योलीवाला का दिखा देसी और विदेशी अंदाज

साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में शामिल 'मिजार्पुरः द मूवी' की रिलीज से पहले इसका पहला गाना 'दो नंबरी' रिलीज हुआ है। इस गाने को ढांडा न्योलीवाला ने लिखा, कंपोज किया और अपनी आवाज दी है। यह ट्रैक उनके बॉलीवुड डेब्यू का भी आगाज है।

गाने में क्या है? : लगभग दो मिनट के गाने में दिखाया गया है कि ढांडा न्योलीवाला गाना गा रहे हैं। गाने में वह ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसमें गाड़ी, बंदूक और हवाई जहाज नजर आ रहे हैं। कई बार वह विदेश में तो कई बार देसी अंदाज में नजर आए हैं।

'मिजार्पुरः द मूवी' दर्शकों को फिर से सीजन 1 की दुनिया में लेकर जाएगी। फिल्म में पहली बार बड़े पर्दे पर गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना भैया (दिव्येंदु) और कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) जैसे फ्रेंचाइजी के सबसे लोकप्रिय किरदारों की वापसी होगी।

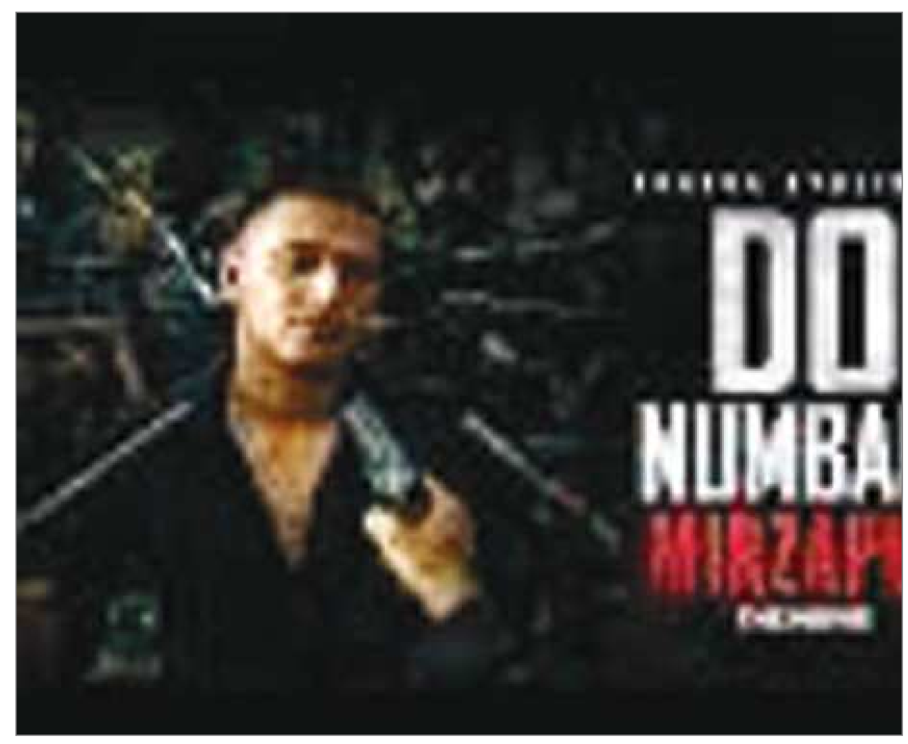

फिल्म की स्टारकास्ट : फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंगशा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

कौन है निर्देशक? : 'मिजार्पुरः द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। वहीं कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी इसके सह-निमार्ता हैं।

यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी।

प्रियंका चोपड़ा ने दिखाया अपना दो रूप, यूजर्स को आया पसंद, कहा, 'आप पर गर्व है'

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर करके फैंस को अपनी घरेलू जिंदगी की एक झलक दिखाई है। इस वीडियो में उनके 'मामा' (माँ) और 'मामासिटा' (बिंदास मां) दोनों ही रूप देखने को मिल रहे हैं। प्रियंका के इस वीडियो ने कई फैंस का दिल जीत लिया है।

वीडियो में क्या खास है? : वीडियो की शुरूआत एक शांत और निजी पल के साथ होती है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी को देवी दुर्गा को समर्पित 'सर्व मंगल मांगल्ये' मंत्र सिखा रही हैं। मां और बेटी के बीच का यह प्यार भरा संवाद प्रियंका के उस 'ममा' वाले रूप को दिखाता है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया है।

प्रियंका का मामासिटा वाला रूपः क्लिप के दूसरे हिस्से में माहौल बदल जाता है। जहां 44 साल की एक्ट्रेस दोस्तों के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करती दिख रही हैं और अपना 'मामासिटा' वाला रूप दिखा रही हैं। ये दोनों पल मिलकर प्रियंका की जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें वह परिवार के साथ शांत समय बिताने और मस्ती भरे पलों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। यूजर्स को पसंद आया अंदाजः कई यूजर्स को प्रियंका का ये वीडियो खूब पसंद आया है। अभिनेत्री नेहा मलिक ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा 'क्यूट मामा, क्यूट मामासिटा।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'देसी गर्ल से देसी मां तक।' एक और यूजर ने लिखा 'आप पर गर्व है। आप प्रेरणा हैं।' एक और यूजर ने लिखा है 'आप दोनों रूपों में कमाल लगती हैं।'

मुश्किलों में घिरे फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो, यूईएफए ने दी केस की धमकी, ट्रंप की शरण में पहुंचे

लंदन : फुटबॉल विश्व कप में निजी निवेशकों को 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का पद छीनने जा रही है। यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन (यूईएफए) ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम भी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। हालांकि इसके बाद इन्फेंटिनो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से समर्थन मांगा है।

करीब 4.2 अरब डॉलर (40,000 करोड़ रुपये) जुटाने की इन्फेंटिनो की विवादित योजना का सभी महाद्वीपों में विरोध हो रहा है। बर्नहैम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह फुटबॉल को आगे ले जाने को सही व्यक्ति हैं। जो योजना पेश की थी, वह दुनिया भर में फुटबॉल से जुड़े लोगों को आपत्तिजनक लगी। ऐसा नहीं कि हम इसे भूलकर आगे बढ़ जाएं, यह स्वीकार्य नहीं है।

वेल्स ने छीना समर्थन, इंग्लैंड भी तैयारी मेंः वेल्स फुटबॉल महासंघ ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के दोबारा चयन के अभियान से समर्थन वापस ले लिया है। वेल्स ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इंग्लिश फुटबॉल संघ ने भी समर्थन वापस लेने की तैयारी कर ली है। दोनों ने इन्फेंटिनो की फीफा विश्वकप जैसे टूर्नामेटों में निजी निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की अधूरी योजना के खिलाफ यह कदम उठाया है।

सिर पर विश्व कप, कोच साहब मना रहे हैं छुट्टी महिला टीम के मुख्य कोच स्जोर्ड मरीन घिरे

नई दिल्लीः भारतीय हॉकी इस समय विवादों से घिरी हुई है। केसरिया जर्सी विवाद के बीच विश्व कप से ठीक पहले मुख्य कोच को छुट्टी देने पर नया हंगामा खड़ा हो गया है। नीदरलैंड व बेल्जियम में विश्व कप 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। लेकिन महिला टीम के मुख्य कोच स्जोर्ड मरीन खिलाड़ियों संग जुटे होने की बजाय पिछले 20 दिन से अवकाश पर हैं।

भारतीय महिला टीम को पहले खिताब की तलाशः सलीमा टेटे की अगुआई वाली महिला टीम अपने पहले खिताब के लिए पसीना बहा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन 12 जुलाई से निजी पारिवारिक कारणों से अवकाश पर हैं और उनके छह अगस्त को नीदरलैंड में टीम से जुड़ने की उम्मीद है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले बंगलूरू में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। फिर 31 जुलाई और एक अगस्त को जर्मनी में अभ्यास मैच खेला और अब टीम नीदरलैंड में अंतिम तैयारी कर रही है। इस दौरान टीम के मुख्य के कोच की गैरमौजूदगी टीम के प्रदर्शन पर असर डाल सकती है। भारत को अपना पहला मुकाबला 16 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलना है। भारतीय महिला टीम का विश्व कप में 1974 में चौथा स्थान श्रेष्ठ प्रदर्शन है।

भारतीय महिला टीम को पहले खिताब की तलाशः सलीमा टेटे की अगुआई वाली महिला टीम अपने पहले खिताब के लिए पसीना बहा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन 12 जुलाई से निजी पारिवारिक कारणों से अवकाश पर हैं और उनके छह अगस्त को नीदरलैंड में टीम से जुड़ने की उम्मीद है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले बंगलूरू में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। फिर 31 जुलाई और एक अगस्त को जर्मनी में अभ्यास मैच खेला और अब टीम नीदरलैंड में अंतिम तैयारी कर रही है।

हॉकी इंडिया और साई ने मंजूर की छुट्टीः रिपोर्ट के मुताबिक, मरीन कि इस छुट्टी को हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) दोनों ने मंजूरी दी है। उनकी अनुपस्थिति में टीम की जिम्मेदारी विश्लेषणात्मक कोच माथियास विला संभाल रहे हैं।

इन्होंने उठाए सवालः पूर्व एफआईएच और हॉकी इंडिया अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा, सबसे पहले तो पुरुष टीम के कार्यकाल में कथित दुर्व्यवहार को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर होने के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त ही नहीं करना चाहिए था। अब विश्व कप जैसे टूनार्मेंट से पहले छुट्टी लेना हॉकी इंडिया के गैर-गंभीर रवैये को दिखाता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान पीआर श्रीजेश का कहना है कि बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। कोच के तौर पर यही वह समय होता है जब पेनल्टी कॉर्नर, सेट-पीस, शूटआउट जैसी रणनीतियों पर अंतिम तैयारी की जाती है।

न्यूज ब्रीफ

असम में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में 3 किशोर गिरफ्तार, फांसी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन

दिसपुरः असम के हैलाकांडी जिले में 15 वर्षीय किशोरी की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे भी कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई है।

पुलिस के अनुसार, मृतका आरोपियों में से एक के साथ रिश्ते में थी। किशोरी का शव राष्ट्रीय राजमार्ग-6 (एनएच-6) के पास स्थित उसके घर में मिला था। परिजनों का आरोप है कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रविवार को पांच युवकों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद सोमवार को 17 से 19 वर्ष आयु के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैलाकांडी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने बताया कि एक आरोपी की उम्र करीब साढ़े 17 वर्ष है। पुलिस ने अदालत से उसे वयस्क मानकर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

मृतका की मां ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य एक दावत में गए थे। वहां किशोरी की अपने चचेरे भाई के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह रात करीब 10:30 बजे अकेले घर लौट आई। लगभग एक घंटे बाद जब परिवार घर पहुंचा तो वह मृत मिली। परिजनों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी घर और परिवार की परिस्थितियों से परिचित थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना के बाद हैलाकांडी और बराक घाटी क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने असम और मिजोरम को जोड़ने वाले एनएच-6 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी देने की मांग की।

जानलेवा बने स्पीड ब्रेकर पर एनएचएआई का बड़ा यू-टर्न, वायरल वीडियो ने खोली पोल, सस्पेंड हुआ प्रोजेक्ट डायरेक्टर

जयपुर : सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए बनाए जाने वाले स्पीड ब्रेकर अगर खुद ही हादसों को दावत देने लगें, तो इसे आप क्या कहेंगे? राजस्थान के नेशनल हाईवे 25 पर ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर भारी बवाल मचा दिया। पृथ्वीपुरा गांव के पास बने बेहद ऊंचे और खतरनाक स्पीड ब्रेकर के वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को न सिर्फ बैकफुट पर आना पड़ा, बल्कि झूठी रिपोर्ट देने वाले अपने ही एक बड़े अधिकारी को सस्पेंड भी करना पड़ा है। आइए जानते हैं कि आखिर सुरक्षा के नाम पर यह कैसा खेल चल रहा था।

कैसे शुरू हुआ विवाद? : राजस्थान के पृथ्वीपुरा गांव के पास एपएच-25 पर हाल ही में कुछ नए स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं। लोगों ने दावा किया कि ये स्पीड ब्रेकर तय मानकों के बिल्कुल उलट और जरूरत से ज्यादा ऊंचे बनाए गए हैं। यूजर्स ने सवाल उठाया कि जिन स्पीड ब्रेकर का काम सड़क सुरक्षा बढ़ाना है, वे ही अगर विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए मौत का फंदा बन जाएं, तो उनकी क्या उपयोगिता रह जाती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई।

एनएचएआई ने पहले झाड़ा पल्ला, दावों को बताया था भ्रामक : विवाद बढ़ता देख शुरूआत में एनएचएआई ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने अपना बचाव करते हुए एक बयान जारी किया और मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह भ्रामक करार दिया। एनएचएआई ने तर्क दिया कि ये स्पीड ब्रेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि के अनुरोध पर और ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। उनका यह भी दावा था कि वायरल हो रहे वीडियो में मौके की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्टरी में भीषण आग, मलबा गिरने से दो दमकलकर्मी शहीद, तीन घायल

नई दिल्लीः ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र ईकोटेक-3 स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली एक फैक्टरी में 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के दौरान फैक्टरी की दीवार और भारी लोहे का बीम अचानक गिरने से दो जांबाज दमकलकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना ईकोटेक-3 इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित क्छत्र्क्क्ट कंपनी परिसर में हुई, जहां इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का निर्माण किया जाता है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की लगभग 10 गाड़ियां (फायर टेंडर्स) तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और लगभग 10 फायर टेंडर मौके पर पहुँचे और आग पर काबू पा लिया।

लोहे के बीम में फँसे फायरफाइटरः आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान, फैक्ट्री की एक साइड की दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया, जिससे फायर सर्विस के पाँच कर्मचारी उसमें फँस गए। घायलों की पहचान हेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, हेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव के तौर पर हुई। पाँचों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने फायरमैन रोहित यादव और हेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी तीन घायल कर्मचारियों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के सीनियर अधिकारी और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। अधिकारी आग लगने के कारण की भी जाँच कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक तीन अन्य लोग घायलः डीसीपी(सेंट्रल नोएडा) शैलेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, सोमवार रात फैक्ट्री में आग लगी। सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुँचीं।

आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान, बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा और लोहे का बीम गिर गया, जिससे फायरफाइटर तीरथपाल सिंह और रोहित यादव की मौत हो गई। इस घटना में फायर सर्विस के तीन अन्य कर्मचारी घायल हो गए।

भारत समेत 60 देशों पर ट्रंप के नए टैरिफ का मामला फिर पहुंचा कोर्ट, अमेरिका के 25 राज्यों ने दायर किया मुकदमा

नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर अमेरिका के भीतर ही बड़ा कानूनी और राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले अमेरिका के 25 राज्यों के एक समूह ने सोमवार को अदालत का रुख किया है। इन राज्यों ने भारत और यूरोपीय संघ (एव) समेत 60 व्यापारिक साझेदार देशों से होने वाले आयात पर लगाए गए नए टैरिफ को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। राज्यों का तर्क है कि ट्रंप प्रशासन इसी तरह के कदमों पर कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद एक बार फिर अपनी कानूनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रहा है। न्यूयॉर्क में वर कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर इस मुकदमे में 10% से 12.5% ??तक के उन टैरिफ को निशाना बनाया गया है, जो पिछले महीने ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत लागू हुए थे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये ड्यूटी उन देशों के खिलाफ हैं जो जबरन मजदूरी से बने सामान के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रहे हैं।

यह मुकदमा ओरेगन और न्यूयॉर्क समेत 25 राज्यों ने दायर किया है, जिनके गवर्नर या अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। राज्यों का तर्क है कि ट्रंप एक अलग कानूनी आधार का इस्तेमाल करके उन बड़े इम्पोर्ट टैक्स को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कोर्ट पहले ही गैर-कानूनी करार दे चुका है। शिकायत के अनुसार, धारा 301 का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोपी खास देशों या उद्योगों को निशाना बनाने के लिए किया गया है - न कि लगभग सभी वर इम्पोर्ट पर व्यापक टैरिफ लगाने के लिए। शिकायत में यह भी तर्क दिया गया है कि प्रशासन जबरन मजदूरी का बहाना बनाकर उन टैरिफ को फिर से लागू कर रहा है जिन्हें कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ओरेगन के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने एक बयान में कहा, हर कदम पर हारने के बावजूद, ट्रंप एक बार फिर कामकाजी परिवारों और ओरेगन के स्थानीय व्यवसायों के लिए और अधिक मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

नए टैरिफ 60 ट्रेडिंग पार्टनर देशों पर लागूः विवादित टैरिफ की घोषणा 24 जुलाई को की गई थी और ये यूरोपीय संघ और भारत समेत 60 ट्रेडिंग पार्टनर देशों से होने वाले इम्पोर्ट पर लागू होते हैं। कुछ देशों को कड़े नियम लागू करने के बाद कम टैरिफ दरें मिलीं। उदाहरण के लिए, प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, भारत के लिए टैरिफ दर 12.5% ??से घटाकर 10% कर दी गई। कुछ खास प्रोडक्ट्स, जैसे तेल, नैचुरल गैस, फर्टिलाइजर और वर-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट के तहत ड्यूटी-फ्री सुविधा पाने वाले सामानों को नए टैरिफ से छूट दी गई।

नए टैरिफ का ऐलान करते हुए वर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने इस कदम का बचाव किया। अमेरिका में लगभग एक सदी से जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के इंपोर्ट पर रोक है और इसे सख्ती से लागू किया जाता है; अब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए भी ऐसा ही करने का समय आ गया है।

ट्रंप ने एक नई कानूनी रणनीति अपनाईः ये टैरिफ ट्रंप के आर्थिक एजेंडा के मुख्य स्तंभों में से एक को बचाने की उनकी नई कोशिश है, क्योंकि इससे पहले के उपायों को कानूनी तौर पर काफी झटके लगे थे। इस साल की शुरूआत में, वर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को बड़े पैमाने पर ग्लोबल टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है, जिससे ट्रंप की एक अहम ट्रेड पहल रद्द हो गई।

इसके जवाब में, ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत दुनिया भर में अस्थायी टैरिफ लगाए। बाद में वर कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने उन लेवी को भी गैर-कानूनी करार दिया, हालांकि प्रशासन की अपील के दौरान वे लागू रहे।

कानूनी चुनौतियों के कारण उन विकल्पों के बाद, प्रशासन ने अब ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 का रुख किया है, एक ऐसा कानून जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से विदेशी सरकारों की अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं का जवाब देने के लिए किया जाता है।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन पर टैरिफ लगाने के लिए इसी प्रावधान का इस्तेमाल किया था, और वे उपाय कानूनी चुनौतियों में टिके रहे क्योंकि वे किसी खास देश को टारगेट करके लगाए गए थे।

कोर्ट से बार-बार झटके मिलने के बावजूद ट्रंप वर मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू करने और ग्लोबल ट्रेड को नया रूप देने के लिए टैरिफ को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। पिछले साल, उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिका का लंबे समय से चला आ रहा ट्रेड डेफिसिट एक राष्ट्रीय आपातकाल है, और आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगभग हर देश से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ लगाए, हालांकि बाद में कोर्ट ने उन उपायों पर रोक लगा दी।

गंगा पर नया डबल-लाइन पुल बनकर तैयार, 4 अक्टूबर तक 384 ट्रेनों का रूट डायवर्ट, 67 रद्द

पटना : त्योहारी सीजन से पहले पूर्व मध्य रेलवे ने बिहारवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। दानापुर रेल मंडल के तहत मोकामा के पास गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित नए रेलवे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हालांकि, इस नए पुल पर ट्रेनों की रफ्तार भरने से पहले इंटरलॉकिंग के काम के चलते यात्रियों को कुछ दिनों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने मेगा ब्लॉक लेते हुए सैकड़ों ट्रेनों का रूट बदल दिया है और कई ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले यह पूरी जानकारी जरूर पढ़ लें।

384 ट्रेनों का बदला रास्ता, 67 गाड़ियां पूरी तरह रद्दः पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे यातायात में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस दौरान कुल 384 महत्वपूर्ण ट्रेनों को उनके तय रूट की जगह परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इसके साथ ही 56 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त (आंशिक समापन) किया जाएगा और 67 ट्रेनें आंशिक रूप से शुरू होंगी। यात्रियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, 20 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों पर कुल 67 ट्रेनें पूरी तरह से निरस्त रहेंगी। सबसे ज्यादा असर 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जिस दिन 36 ट्रेनें रद्द रहेंगी।

60 साल पुराने सिंगल लाइन पुल के जाम से मिलेगी निजातः मोकामा और बरौनी के बीच गंगा नदी पर मौजूद मौजूदा 1.9 किलोमीटर लंबा रेल-सह-सड़क राजेन्द्र पुल 1959 में बनाया गया था। इस पुराने पुल पर केवल सिंगल लाइन होने और तकनीकी बाधाओं के कारण लाइन का दोहरीकरण संभव नहीं था। पिछले छह दशकों में ट्रेनों की संख्या और यातायात कई गुना बढ़ गया, जिससे लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों को बरौनी से पहले ही छोटे स्टेशनों पर घंटों आउटर पर रोकना पड़ता था। यात्रियों की इसी भारी परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने नए डबल लाइन पुल का प्रस्ताव मंजूर किया था, जो अब बनकर तैयार है।

पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास, 1491 करोड़ की आई लागतः इस महाप्रोजेक्ट को 2015-16 के रेल बजट में मंजूरी मिली थी, जिसकी अनुमानित लागत 1491.47 करोड़ रुपये तय की गई थी। इसके बाद 12 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए पुल की आधारशिला रखी थी। यह नया डबल लाइन रेल पुल पुराने राजेन्द्र पुल के ठीक समानांतर पटना की दिशा में महज 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। मुख्य पुल की लंबाई लगभग 1.9 किलोमीटर है, जबकि एप्रोच लाइन को मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 14 किलोमीटर है।

पुराने स्टेशनों से ही जुड़ेगा नया रेल नेटवर्कः इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी पर मुख्य पुल के अलावा नौ छोटे पुल, दो सड़क ऊपरी पुल और तीन रेल ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। रेलवे ने इस नए पुल का खाका इस तरह से तैयार किया है ताकि मौजूदा पुल के एप्रोच में कम से कम बदलाव करना पड़े। यह नया पुल भी पुराने नेटवर्क की तरह उत्तर में स्थित हाथीदह, टाल और रामपुर डुमरा स्टेशनों को दक्षिण में स्थित राजेन्द्र पुल और बरौनी स्टेशनों से सीधा जोड़ेगा। इंटरलॉकिंग का काम पूरा होते ही इस रूट पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और यात्री बिना किसी देरी के अपने सफर का आनंद ले सकेंगे।

एक्ट्रेस तृषा पर विवादित बयान मामले में बड़ा एक्शन पुलिस ने पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे को किया गिरफ्तार

तंजावुर : तमिलनाडु की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर की गई एक कथित आपत्तिजनक और दोअर्थी टिप्पणी के मामले में राज्य के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके के कद्दावर नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय की सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम(टीवीके) द्वारा पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) में सख्त शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी से पहले तंजावुर में उस घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जहां उदयनिधि ठहरे हुए थे।

जनसभा में लगे तृषा-तृषाके नारे और फिर बिगड़े बोलः यह पूरा हाई-प्रोफाइल विवाद तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक जनसभा के दौरान शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व उपमुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन जब मंच से अपना भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अचानक तृषा, तृषा के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर उदयनिधि ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और भीड़ की तरफ देखते हुए कहा कि ह्यपानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, उन्हें वहां जरूर पहुंचना चाहिए। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी सफाई में यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनका इशारा कावेरी नदी के पानी की तरफ था, लेकिन तब तक उनका यह बयान सियासी तौर पर बड़ा तूल पकड़ चुका था।

टीवीके पर अश्लीलता का आरोप और पुलिस का कड़ा एक्शनः उदयनिधि की इस विवादित टिप्पणी पर सत्ताधारी दल टीवीके ने कड़ा ऐतराज जताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीवीके का सीधा आरोप है कि उदयनिधि स्टालिन ने तृषा-तृषा के नारों का जवाब बेहद अश्लील और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी से दिया है, जो सरेआम एक महिला का अपमान है। इसके तुरंत बाद, तंजावुर में टीवीके की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट महिला विंग की संयोजक एस. भैरवी ने तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पहले उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी आधिकारिक गिरफ्तारी कर ली गई।

लिव-इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना शादी साथ रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा 498ए का संरक्षण

नई दिल्ली : लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब अगर कोई जोड़ा बिना शादी किए पति-पत्नी की तरह साथ रह रहा है, तो उनके रिश्ते पर भी घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े कड़े कानून लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए का दायरा बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि शादी जैसे रिश्ते में रहने वाली महिलाओं के साथ अगर जुल्म या क्रूरता होती है, तो उनके पुरुष पार्टनर और उसके रिश्तेदारों पर भी 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा।

लिव-इन रिश्तों पर ही लागू होगा नया नियमः जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस बड़े फैसले पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि धारा 498ए का डंडा हर लिव-इन रिलेशनशिप पर नहीं चलेगा। यह नियम केवल उन्हीं रिश्तों पर लागू होगा जो पूरी तरह से शादी जैसे रिश्ते की श्रेणी में आते हैं। अदालत के अनुसार, ऐसे संबंधों में भविष्य में विवाह करने का इरादा होना एक बहुत जरूरी तत्व है। साथ ही, यह कानूनी सुरक्षा सिर्फ उन मामलों में मिलेगी जहां दो बालिग अपनी सहमति से एक साथ रह रहे हों।

सीधे गिरफ्तारी नहीं, पहले होगी कार्रवाईः इस फैसले के बाद पुरुषों के मन में उठ रहे गिरफ्तारी के डर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि शादी जैसे लिव-इन रिलेशनशिप में क्रूरता का आरोप लगने पर पुलिस सीधे तौर पर आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती। किसी भी आरोपी पुरुष या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को प्रारंभिक जांच करनी होगी और गिरफ्तारी से जुड़े सभी कानूनी सुरक्षा प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि 498ए की यह नई व्याख्या सिर्फ इसी धारा तक सीमित रहेगी। अदालत की दो टूक- महिलाओं के बीच भेदभाव असंवैधानिकः इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का भी प्रमुखता से जिक्र किया। अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा रोकने के मामले में एक विवाहित महिला और शादी जैसे लिव-इन रिश्ते में रहने वाली महिला के बीच फर्क करना बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट का मानना है कि कोई भी व्यक्ति रिश्ते की शुरूआत में यह नहीं सोचता कि उसके साथ भविष्य में जुल्म होगा, इसलिए मुसीबत के समय हर महिला को उचित कानूनी संरक्षण मिलना ही चाहिए।

किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे प्रशांत किशोर?...बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत के बाद किया बड़ा ऐलान

पटनाः जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे दलों के असंतुष्ट समर्थकों के सहयोग से संभव हो सकी।

भाजपा के नीरज कुमार को 19 हजार से अधिक मतों से हराने के बाद पत्रकारों से बातचीत में किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बांकीपुर सीट पर 1995 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा था, लेकिन इस उपचुनाव में जन सुराज ने पहली बार यहां पर जीत दर्ज की। गठबंधन की संभावना और चुनाव अकेले लड़ने की अपनी पहले की रणनीति पर पुनर्विचार किए जाने संबंधी सवाल पर किशोर ने कहा, "हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे।

उत्तरी कोयल (मंडल डैम) परियोजना को मिलेगी रफ्तार, अक्टूबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद

सांसद विष्णु दयाल राम ने वैप्कोस की सीएमडी से की मुलाकात, नई एजेंसी से कराया जाएगा शेष कार्य

मेट्रोरेज संवाददाता

मेदिनीनगर : पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम ने मंगलवार को नई दिल्ली में वैप्कोस लिमिटेड की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे से मुलाकात कर बहुप्रतीक्षित उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान सांसद ने परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लेफ्ट मेन कैनाल के लिए 0.61 एकड़ भूमि का मुआवजा वितरण अभी शेष है। वहीं राइट मेन कैनाल का लगभग 14 किलोमीटर निर्माण कार्य पूरा किया जाना बाकी है।

सांसद ने बताया कि दोनों कैनालों का निर्माण कार्य कर रही विक्रमादित्य कंपनी की धीमी कार्यप्रणाली को देखते हुए उसकी निविदा निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर 2026 तक नई निर्माण एजेंसी का चयन कर कार्य आवंटित किया जाएगा, जिससे परियोजना की गति तेज

होगी। उन्होंने कहा कि मुख्य मंडल डैम से संबंधित हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल और सिविल कार्यों के टेंडर एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर 2027 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

सांसद ने बताया कि परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और वैप्कोस लिमिटेड द्वारा की जा रही है, ताकि सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूरे हो सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 तक उत्तरी कोयल (मंडल डैम) परियोजना का निर्माण पूरा होने से पलामू प्रमंडल के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी।

न्यूज IN ब्रीफ

मतदाता सूची में केवल नाम होना प्रयाप्त नही, मतदाता सूची के प्रत्येक बिंदु की जांच करें : निसार खान

हजारीबाग : जिला कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सह जिला कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष निसार खान ने हजारीबाग जिले के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत प्रत्येक नागरिक का मतदान का अधिकार है । इसलिए पांच अगस्त के बाद एसआईआर 2026 का ड्राफ मतदाता सूचि प्रकाशित हो, तब केवल यह देखकर वापस न लौटें कि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, बल्कि अपने नाम से संबंधित प्रत्येक बिंदु की गंभीरता से जांच अवश्य करें । उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि मतदाता सूची में तो दर्ज रहता है, लेकिन नाम की वर्तनी, फोटो, पता, मतदान केन्द्र, भाग संख्या, क्रमांक संख्या अथवा अन्य विवरणों में त्रुटियां रह जाती है । ऐसी छोटी-छोटी गलतियां भविष्य में मतदान के समय अनावश्यक परेशानियों का कारण बन सकती है । इसलिए प्रत्येक मतदाता का यह दायित्व है कि वह अपने विवरण की पूरी जांच कर समय रहते अनावश्यक सुधार कराए । खान ने कहा कि मतदाताओं को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूची में उनके नाम की स्पेलिंग सही हो, फोटो उन्हीं को हो, स्थायी पता सही दर्ज हो, भाग संख्या एवं क्रमांक संख्या सही अंकित हो, तथा कोई विशेष टिप्पणी गलत तरिके से दर्ज न हो । यदि इनमे से किसी बिंदु पर त्रृटि दिखाई दती है तो संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी यह बूथ स्तर पर के अधिकारी (बीएलओ) से सम्पर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल सुधार करा लें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता मतदान के अधिकार सं वंचित न रह जाए ।

चक्रधरपुर न्यू चांदमारी शिवभक्त मंडल बाबा नगरी देवघर पहुंचे और चढ़ाया बाबा को जल

संवाददाता : न्यू चांदमारी शिवभक्त मंडल बाबा नगरी देवघर पहुंचे और बाबा को जल अर्पित किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने कहा कि बाबा के दरबार में आकर असीम आनंद की अनुभूति होती है।इस भक्त मंडली में विनोद जयसवाल, गुड्डु सिंह,नीरू साव के अलावा अन्य सदस्यगण भी शामिल हैं।

जाति, आय व न्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए लगे विशेष कैंप

सिमडेगा : कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देश के आलोक में जिले के सभी अंचल कार्यालयों में आज विशेष कैंप का आयोजन किया गया। यह अभियान 03 अगस्त से 07 अगस्त 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत आमजनों को जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (एहर) प्रमाण-पत्र निर्गत एवं वितरित किए जा रहे हैं।

कैंप में नए आवेदन प्राप्त करने के साथ-साथ पूर्व से लंबित आवेदनों का भी निष्पादन करते हुए पात्र लाभुकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान के सफल संचालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कैंप की नियमित निगरानी एवं प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जायेगी साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। आज के इस विशेष कैंप में कुल 1525 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से कुल 422 आवेदन का निष्पादन भी किया गया। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक निर्धारित तिथि एवं कार्यालय अवधि में संबंधित अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को प्रमाण-पत्र की सुविधा सरल एवं त्वरित रूप से उपलब्ध कराना है।

स्कूली छात्रों के बीच मारपीट, लोगों ने चापड़ और चाकू के साथ पकड़ा

जमशेदपुर : बिरसानगर थाना अंतर्गत नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रों में मारपीट हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और दो लोगों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक चापड़ और चाकू बरामद किया गया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाना ले गई जहां सभी से पूछताछ कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार को सातवीं और आठवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच झड़प हुई थी। इसी बात को लेकर आज सातवीं कक्षा के छात्र ने बाहरी लोगों को बुला लिया। स्कूल की छुट्टी होते ही छात्रों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान पीड़ित ने स्कूल में घुसकर अपनी जान बचाई। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बोड़ाम बाजार से नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी व बारियादा में मोबाइल की चोरी

पटमदा : बोड़ाम थाना से करीब 500 मीटर दूर बोड़ाम बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान और बारियादा गांव की एक मोबाइल दुकान में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने छत काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी दुकान से करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर, 15 ग्राम सोना, 25 हजार रुपये नकद समेत लगभग 5 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली गई। वहीं मोबाइल दुकान से 31 हजार रुपये नकद और कई मोबाइल फोन गायब मिले।मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे ज्वेलरी व्यवसायी दीपक स्वर्णकार उर्फ डब्लू ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि चोर टीन और एस्बेस्टस की छत काटकर दुकान में घुसे तथा पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए।दोनों पीड़ित दुकानदारों ने बोड़ाम थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

देवघर उपायुक्त के बेहतर और उत्कृष्ट प्रयास देवघर का सावन रच रहा इतिहास

बिनय मिश्रा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2019 बैच के लोकप्रिय, कर्मठ और बेहतर कार्य के लिए पहचाने जाने वाले सौरभ कुमार भुवनिया खूंटी के पश्चात देवघर के उपायुक्त बनाए गए। देवघर में प्रख्यात श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों और भक्तजनों तथा श्रद्धालुओं की सुधि और सुविधा बेहतर ढंग से व्यवस्थित कराने की उत्कृष्ट कार्य भी संतोषजनक और बेहतर माना जा रहा है। उपायुक्त स्वयं जिला प्रशासन के साथ इस मेले की व्यापक रूप से तैयारी में पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं जिला प्रशासन का बेहतर सामंजस्य भी काफी सराहनीय और प्रशंसनीय है। 30 जुलाई से प्रारंभ हुए इस श्रावणी मेले की विधि व्यवस्था तथा सभी लोगों को सहज रूप से देव नगरी में सुलभ तरीके से भगवान

भोलेनाथ के दर्शन हो इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। विदित हो कि श्री भुवनिया रांची के लोकप्रिय उप विकास आयुक्त भी रह चुके हैं तथा खूंटी के उपायुक्त भी रहे हैं । ऐसे आईएएस अधिकारी से राज्य और जिला दोनों गौरवान्वित होता है।

गरीब परिवार का जर्जर मकान देख विचलित हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी

तत्काल आवास निर्माण केदिए निर्देश, राशन कम बांटने पर डीलर को लगाई सख्त फटकार

संवाददाता

बरडीहा (गढ़वा) : प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने आज प्रातः 6:00 बजे से बरडीहा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का सघन स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरूआत उन्होंने सर्वप्रथम ब्लॉक कॉलोनी से की, जहाँ उन्होंने आवासों एवं आवागमन के रास्तों का जायजा लिया। कर्मियों द्वारा मार्ग न होने की समस्या बताए जाने पर बीडीओ ने जल्द से जल्द पक्की सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया।

नाद-खूंटा हटवाकर आम रास्ता कराया मुक्त

इसके पश्चात कुन्दरहे मोड़ से पहले मुखिया उमेश प्रजापति के नेतृत्व में एकत्रित 50-60 ग्रामीणों के आग्रह पर बीडीओ कुन्दरहे गांव पहुँचे। गांव के मुख्य रास्ते पर मवेशियों को बांधकर एवं नाद-खूंटा लगाकर किए गए अतिक्रमण को बीडीओ ने मौके पर ही हटवाया और आम रास्ते को सुचारू रूप से बहाल कराया।

हृदय विदारक दृश्यः जर्जर मकान और दबंगों की साजिश उजागर

निरीक्षण के दौरान बीडीओ प्रवीण कुमार सिंह की नजर एक अत्यंत जर्जर मकान पर पड़ी, जो बरसात में कभी भी धराशायी हो सकता था। पूछने पर कुछ असमाजिक तत्वों ने भ्रमित करने का प्रयास किया कि घर खाली है। परंतु सच्चाई सामने आते ही बीडीओ परिवार की अनुमति से घर के आंगन में दाखिल हुए।

पूछताछ में गृहस्वामी राजेंद्र सिंह के परिजनों ने बताया कि उन्हें आवास स्वीकृत हुआ है, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा धोखे से जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का दावा कर निर्माण कार्य रोका जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया।

₹मानवता के खिलाफ है काम रोकना, हर हाल में बनेगा गरीब का घर₹

मौके से ही बीडीओ ने आवास कोऑर्डिनेटर रवि रंजन को अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराने का कड़ा निर्देश दिया। बीडीओ प्रवीण कुमार सिंह ने कड़े शब्दों में कहाः

> ₹जमीन विवाद का बहाना बनाकर किसी गरीब को बेघर नहीं रखा जा सकता। यह मानवता के खिलाफ है। अगर यह जर्जर घर गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी ताकत इस गरीब का घर बनने से नहीं रोक सकती। जमीन विवाद का निष्पादन मैं स्वयं (अंचल अधिकारी के रूप में) करूँगा, लेकिन निर्माण कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए।

बीडीओ के इस कड़े व मानवीय रुख से प्रभावित होकर ग्रामीणों में भी एकजुटता दिखी। मौके पर ही ग्रामीणों ने स्वतः आगे आकर मदद की घोषणा की–किसी ने एक ट्रैक्टर छरी, किसी ने बालू तो किसी ने सीमेंट देने का संकल्प लिया।

स्कूल, आंगनबाड़ी और खेल मैदान का निरीक्षण

आगे बढ़ते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गांव के बच्चों के खेल मैदान एवं स्थानीय विद्यालय का जायजा लिया, जहाँ साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने उपस्थित बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी पढ़ाई-लिखाई की जानकारी ली।

राशन में कटौती पर डीलर को कड़ी हिदायत

निरीक्षण के अंतिम चरण में बीडीओ 'अनीता स्वयं सहायता समूह' द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली (डीलर) की दुकान पर पहुँचे। वहाँ लाभुकों से राशन में कटौती (कम तोलने) की शिकायत मिलने पर बीडीओ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डीलर को सख्त निर्देश दिए।

वज्रपात से युवक की मौत, महिला गंभीर

धनबाद : सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार में सोमवार की दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में पास खड़ी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना दोपहर करीब तीन बजे बारिश शुरू होने से ठीक पहले हुई। जानकारी के अनुसार नंद किशोर का 22 वर्षीय पुत्र अमन कुमार अपने फ्लैट की छत पर गया था। उसी समय उसी फ्लैट में रहनेवाले संजय कुमार की 40 वर्षीय पत्नी सोनी देवी भी छत पर मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ। अमन और सोनी देवी इसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद अमन कुमार को मृत घोषित कर दिया। सोनी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही कोलाकुसमा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की इमरजेंसी पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। इससे कुछ देर के लिए अफरातफरी और हंगामे जैसी स्थिति बन गई। भीड़ के कारण अन्य मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी हुई। बाद में होमगार्ड के जवानों ने लोगों को समझाकर इमरजेंसी से बाहर निकाला। इसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। विस्थापन के बाद कुसुम विहार में बसा था परिवार। स्थानीय लोगों के अनुसार अमन का परिवार पहले भौंरा में रहता था। वहीं घायल सोनी देवी का परिवार अंगारपथरा का निवासी था। करीब एक वर्ष पहले दोनों परिवार विस्थापितों के लिए कुसुम विहार में बने सरकारी क्वार्टर में आकर बस गए थे।

नहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत, गांव में पसरा मातम

मोहम्मदगंज : मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बीरधवर गांव स्थित नोनिया टोला में सोमवार सुबह नहर में डूबने से 60 वर्षीय खेदरू चौहान की मौत हो गई। बताया गया कि वह घर के समीप नहर में स्नान करने गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना पर थाना प्रभारी नारायण सोरेन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है।

कल महागामा में आयोजित होगा जनसंवाद कार्यक्रम उपायुक्त लोकेश मिश्रा सुनेंगे आमजनों की समस्याएं

विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी रहेंगे उपस्थित

जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक नागरिकों से कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव रखने की अपील की

बिनय मिश्रा

जिला प्रशासन, गोड्डा द्वारा आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से दिनांक 05 अगस्त 2026 (बुधवार) को महागामा प्रखंड सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम अपराह्न 3:00 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री लोकेश मिश्रा करेंगे।*

जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से महागामा अनुमंडल क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम में प्राप्त मामलों की सुनवाई उपायुक्त द्वारा स्वयं की जाएगी तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, ताकि समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में राजस्व, आपूर्ति, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, ग्रामीण विकास, नगर पंचायत, कृषि, भूमि संबंधी मामलों सहित अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं पर भी सुनवाई की जाएगी। संबंधित विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिससे प्राप्त शिकायतों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री लोकेश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जनसंवाद कार्यक्रम प्रशासन एवं नागरिकों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी मंच है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं बिना किसी मध्यस्थता के सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलता है तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक जनोन्मुख एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

उन्होंने महागामा अनुमंडल क्षेत्र के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों एवं युवाओं से अपील की कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं रचनात्मक सुझावों से प्रशासन को अवगत कराएं।

नगर पंचायत, महागामा द्वारा भी क्षेत्र के सभी नागरिकों से जनसंवाद कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान किया जा सके तथा प्रशासन एवं जनता के बीच संवाद और विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

कार्यक्रम का विवरण :-

तिथि : 05 अगस्त 2026 (बुधवार)
समय : अपराह्न 3:00 बजे से 4:30 बजे तक स्थान : प्रखंड सभागार, महागामा

जिला प्रशासन, गोड्डा ने महागामा अनुमंडल क्षेत्र के सभी नागरिकों से जनसंवाद कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है, ताकि प्रशासन एवं जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो तथा जनसमस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।